

नवोदय

पंजाब एण्ड सिंध बैंक की तिमाही गृह पत्रिका | सितंबर 2024

१६ श्री बागिचावु नो वी इउरि



Navodaya

Punjab & Sind Bank Quarterly House Journal | September 2024



१६ श्री बागिचावु नो वी इउरि
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
(Punjab & Sind Bank / A Govt. of India Undertaking)



Our Bank presented

Dividend Cheque to Honorable Minister for Finance & Corporate Affairs

Smt. Nirmala Sitharaman



Shri Swarup Kumar Saha (MD & CEO), Shri Ravi Mehra (Executive Director), Shri Rajeeva (Executive Director), Smt. M.G. Jayasree (MoF Nominee Director) and Shri Arnab Goswamy (Chief Financial Officer) were present there to handover the dividend cheque.



(केवल आंतरिक वितरण हेतु)

पंजाब कार्यालय, बैंक हाउस, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008
Head Office, Bank House, 21, Rajendra Place, New Delhi - 110008

E-mail: editor.navodaya@psb.co.in

मुख्य संरक्षक/Chief Custodian

श्री स्वरूप कुमार साहा

Shri Swarup Kumar Saha

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी / MD & CEO

संरक्षक / Custodian

श्री रवि मेहरा

Shri Ravi Mehra

कार्यपालक निदेशक / Executive Director

श्री राजीवा

Shri Rajeeva

कार्यपालक निदेशक / Executive Director

मुख्य संपादक / Chief Editor

श्री गजराज देवी सिंह ठाकुर

Shri Gajraj Devi Singh Thakur

महाप्रबंधक / General Manager

संपादक मंडल / Editorial Board

श्री राजेश सी पांडे

Shri Rajesh C Pandey

महाप्रबंधक / General Manager

श्री निखिल शर्मा

Shri Nikhil Sharma

मुख्य प्रबंधक / Chief Manager

श्रीमती भारती

Smt. Bharati

प्रबंधक / Manager

पंजाब एण्ड सिंध बैंक गृह पत्रिका में प्रकाशित सामग्री में दिए गए विचार, संबंधित लेखक के अपने हैं। पंजाब एण्ड सिंध बैंक का प्रकाशित विचारों से सहमत होना ज़रूरी नहीं है। सामग्री की मौलिकता एवं कॉपी राइट अधिकारों के प्रति भी लेखक स्वयं उत्तरदायी है।

मुद्रक : जैना ऑफसेट प्रिंटर्स

ए 33/2, साइट-4, साहिबाबाद इंडस्ट्रीयल एरिया,
गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश

फोन नं. : 98112 69844

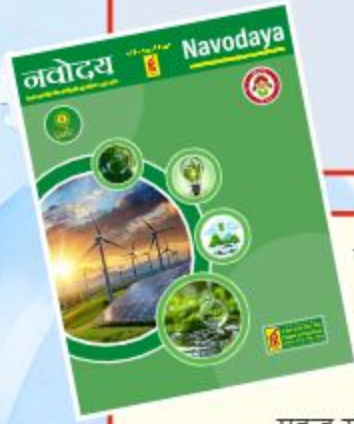
ई-मेल: jainaoffsetprinters@gmail.com

विषयसूची/Index

1.	संपादक मंडल/विषय-सूची	1
2.	शुभकामनाएं एवं सुझाव	2
3.	संपादकीय	3
4.	Money and Wealth	4-6
5.	स्वतंत्रता दिवस समारोह	7
6.	आज का व्यवसाय प्रबंधन	8-9
7.	Branch Incharges Meeting, Zonal Office Chandigarh	10
8.	Highlights of Bank performance of September 2024	11
9.	Zone performance as on 30.09.2024	12-13
10.	बैंकिंग उद्योग की चुनौतियां एवं निवारण	14-16
11.	Inauguration of New Premises of Branch	16
12.	स्वच्छता ही सेवा 2024	17
13.	RBI's Latest Guideline on Wilful Default and Wilful Defaulter	18-19
14.	बैंक के अंचल कार्यालयों में स्वच्छता दिवस का आयोजन	20-21
15.	डिपोजिट मोबेलाइजेशन के अंतर्गत वॉकथॉन का आयोजन	22-23
16.	Cyber Crime: A hole in the boat of Banking Industry and The Way Forward	24-28
17.	MoU Signed with PAU and PCSOA	29
18.	चीन में बढ़ते आर्थिक संकट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव	30-32
19.	Branch Incharges Meeting, Zonal Office Bareilly	33
20.	Important Circulars of the Bank	34-35
21.	World Food India 2024	36
22.	International Trade Expo	37
23.	डिजिटल लेन-देन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव	38-40
24.	Move to Market Campaign drive	41
25.	Free health check-up Camp	41
26.	शेर-ए-पंजाब महाराजा रणजीत सिंह (पंजाबी भाषा)	42-44

शुभकामनाएं एवं सुझाव / Letter to the Editor

नवोदय का यह नवीन अंक प्राप्त हुआ एवं पत्रिका नए रंगों को अपने में संजोए हुए प्रतीत हुई। पत्रिका में विषय बड़े ही मनोरम एवं विचारणीय है जो आपको एक बार सोचने पर मजबूर करते हैं चाहे वो 'जीवन में रिश्तों का महत्व हो' या 'समय का प्रवाह: एक बहता हुआ उपहार' अथवा 'Practising Gratitude in Life' जैसे आलेख हो। वहीं पत्रिका में बैंक के विभिन्न अंचल कार्यालयों में बैंक के 117वें स्थापना दिवस के आयोजन की झलकियां तथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विभिन्न अंचल कार्यालयों में की गई गतिविधियों की प्रस्तुति बड़े ही आकर्षक ढंग से की गई है। नवोदय के इस अंक के सफल प्रकाशन पर प्रकाशन मण्डल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।



गुरदीप
आंचलिक प्रबंधक
अंचल कार्यालय चेन्नई

सर्वप्रथम पत्रिका के कुशल एवं सफल संपादन हेतु हमारी ओर से शुभकामनाएं एवं आभार स्वीकार करें। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पत्रिका के सारगर्भित संकलन, कुशल सम्पादन, गुणवत्ता सम्पन्न प्रकाशन के लिए संपादक मण्डल अभिनन्दनीय है। पत्रिका में वर्तमान परिदृश्य के विभिन्न विषयों को समेटा गया है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता जलवायु परिवर्तन, Time Management, जीवन में रिश्तों का महत्व समसामयिक चुनौतियों से हमारा परिचय कराते हैं। इसके अतिरिक्त पत्रिका की अन्य लेखन सामग्री भी अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण जानकारियों से परिपूर्ण है। पत्रिका के सफल संपादन के लिए संपूर्ण संपादकीय समूह को बहुत-बहुत बधाई एवं आगामी अंक हेतु शुभकामनाएं!



राकेश कुमार यादव
आंचलिक प्रबंधक
अंचल कार्यालय गुरदासपुर

बैंक की तिमाही पत्रिका "नवोदय" के जून, 2024 अंक की प्राप्ति हुई, जिसके लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। पत्रिका में प्रकाशित सामग्री हमेशा की तरह बहुत ही आर्कषक एवं प्रेरणादायक लगी। पत्रिका में प्रकाशित रचनाएं जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता जलवायु परिवर्तन, जीवन में रिश्तों का महत्व, समय का प्रवाह: एक बहता हुआ उपहार आदि रचनाओं ने हृदय में विशेष स्थान बनाया। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी में प्रकाशित रचनाएं जैसे Navigating the rural frontier – A personal account, Practising Gratitude in Life & Customer Service and customer centricity आदि भी बहुत अच्छी लगी। इस पत्रिका में प्रकाशित छायाचित्रों के माध्यम से बैंक के प्रधान कार्यालय एवं विभिन्न अंचल कार्यालयों में हो रही अन्य गतिविधियों के बारे में भी जानकारी मिली। मैं पत्रिका के सफल प्रकाशन एवं इस पत्रिका के माध्यम से बैंक को प्राप्त विभिन्न उपलब्धियों हेतु पत्रिका के संपादक मंडल/ प्रकाशक को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ।



अनिल कुमार
आंचलिक प्रबंधक
अंचल कार्यालय पंचकूला



संपादकीय



प्रिय साथियो,

किसी भी संस्था की सफलता उसकी कार्यप्रणाली एवं नीतियों के कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। हम एक ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जिसका सीधा संबंध ग्राहक संतुष्टि से है। ऐसे में ग्राहक सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे-जैसे दुनिया तकनीकी युग की ओर बढ़ रही है, ग्राहक चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान तुरंत हो जाए। इस तकनीकी क्रांति ने न केवल ग्राहकों को जागरूक किया है बल्कि वे तकनीकी रूप से अत्यंत सजग भी हो गये हैं। वे अब बैंकिंग की बारिकियों को भी बखूबी समझते हैं। इसलिए अब ग्राहकों को संतुष्ट करना थोड़ा कठिन तो है किंतु दुष्कर नहीं। यह ग्राहकों के विचारों एवं व्यवहार में एक बड़ा परिवर्तन है। हमें इसके साथ कदम-ताल करके चलना होगा। हमें तकनीकी रूप में सजग होने के साथ-साथ ग्राहकों की मनःस्थिति को भी समझने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें तकनीकी सशक्ता तथा साइबर सुरक्षा के प्रति स्वयं सचेत होना है और ग्राहकों को भी सचेत करना है। इस प्रकार के क्रियाकलापों से हम ग्राहकों को साइबर सुरक्षा के खतरों के विरुद्ध तैयार कर उनके विश्वासपात्र बन सकते हैं। इस विश्वास के बल पर ही हम उन्हें अपने बैंक से जोड़कर व्यवसाय में वृद्धि कर सकते हैं। ग्राहक संतुष्टि आज के प्रतिस्पर्धी उद्योग में आगे बढ़ने और उत्कृष्टता प्राप्त करने की कुंजी है।

लें संकल्प सृजन का मन में, उम्मीदों से हो भरपूर,
धुन के पक्के उस राही से, मंज़िल है फिर कितनी दूर।

गृह पत्रिका नवोदय भी इस दिशा में कार्य कर रही है। गृह पत्रिका नवोदय अपने विचारों और अनुभवों को दूसरों तक जोड़ने का एक साझा प्रयास है। इसी उद्देश्य से पत्रिका में अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं रोचक लेख एवं कार्टून को भी समाहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त गृह पत्रिका नवोदय के इस अंक में मुख्य रूप से बैंक में आयोजित विभिन्न गतिविधियों, बैंक के विभिन्न उत्पादों, नीतियों, महत्वपूर्ण परिपत्रों सहित आज का व्यवसाय प्रबंधन, wilful defaulter, Money & Wealth, Cyber-crime case study आदि लेख भी समाहित किए गए हैं, जो हमारी जानकारी को पोषित करते हैं। इसलिए आप सभी अपने विचारों को पत्रिका के माध्यम से साझा करते रहें।

मुझे विश्वास है कि आप इसे उपयोगी और सूचनाप्रद पाएंगे। बैंकिंग के विविध पहलुओं को समेटे यह पत्रिका आपको कैसी लगी, इसके अनवरत सुधार की दिशा में आपकी प्रतिक्रिया एवं सुझावों का हमें सदैव इंतजार रहेगा।

(गजराज देवी सिंह ठाकुर)
महाप्रबंधक एवं मुख्य संपादक

MONEY AND WEALTH



Dr. Charanjit Singh

We have all heard of money and wealth. Money makes the mare go; reads an English phrase. Consider another one we learnt at school. 'Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise'. Notice that of the two phrases, one talks of money while the other mentions wealth and exhorts us to aim to be wealthy in life; not moneyed.

So, is money and wealth the same thing or are they different? For most of us the concept and understanding about the precise meaning of the two are hazy. The economists, who are experts in such matters, tell us that they are related but not the same thing. Money and wealth are not synonyms. Instinctively too, it is obvious to common people that in a modern society wealth is regarded superior to money. Let us understand the distinction between the two.

To understand the difference between money and wealth, consider the example of a salaried person who receives a fixed sum of money as salary at the end of each month. He pays all his bills, rents, travel, school fees, entertainment, health bills and other expenses from the money he receives as his salary. Assume he has some money left at the end of the month, after meeting all his expenses. We call this as his savings which he puts in his bank account. This is the money he can call as his own. His savings are his wealth.

If he saves some money from his salary each month and deposits in his bank account, then over time his savings in the bank will grow as his savings will now earn interest. He can choose the method of keeping his money in the bank. He can use savings account or he can choose the fixed deposits, whereby he deposits his savings with his bank for a fixed period and the bank pays him interest. In this way his savings begin to earn and grow.

We say that his savings each month are his wealth. His wealth



will grow with time because the saving each month will get added to his 'wealth' and the interest earned on the amount in his bank account will also increase. This is one example. There are other methods of investing his savings, which may earn him more.

We see that the salary earned by the man in our example is money but all of it is not wealth. He will spend most of the money received as salary to pay for the goods and services essential to run his household. What he receives as salary is money. It is compensation for the services he renders to his employer. But it is only what he saves from his salary after paying all living expenses that really belongs to him. This constitutes his wealth.

We can extend the example to other people in society like shop keepers, skilled workers or those who are self-employed. We see that in their cases too, all money they receive is not wealth. They too must meet their household and other essential expenses from their incomes. What remains will be their savings. It is only what is left after meeting all expenses that will count as their wealth. If they invest their 'wealth' wisely, it will begin to earn and their 'wealth' will grow with time.

Money is a medium of exchange, usually the currency of a country. It is used by people and entities to pay for goods and services, and to repay loans. In ancient human societies, barter was the practice followed by people to pay for goods and services. In those days, the payment in the international trade were accepted in gold and silver. As the civilisations and their human societies progressed, currency was invented. It has made the financial transactions simple and easy.

Over the centuries the currency has undergone improvements. It has taken the form of metal coins and paper money. We use them today in our daily cash transactions at the market place. In the last few decades advance in computer technology has influenced money and currency. The money transactions among the public and institutions are now more and more in the digital form and less and less in hard currency.

In the developed and advanced countries, the digital financial transactions have almost fully replaced the cash. These societies are close to becoming cashless. In the last couple of decades, our own government has taken steps to popularise the use of digital money rather than cash. This has been made easy by the invention of smart phones. The digital financial transactions have become popular in India too as more and more people embrace them.

In practice, common people use both, cash and digital money, for transactions at the market place in their daily lives. Salaries, wages, payment for goods and services and purchases at market place are examples of money paid as consideration for the transactions. The variety of such everyday money transactions in a modern human society is multifarious.

We have seen that money provides a sense of security and convenience, but it doesn't necessarily equate to wealth. Wealth is regarded as superior to money. Wealth is something which commands goods and services at will. If a person has adequate wealth, then, barring some exceptions, he or she can acquire whatever he or she wishes to; tangible or intangible. Wealth in ancient Indian texts is also called 'sarab sadhan', meaning it can solve almost all problems in life.

Wealth is more than money. Land, and even livestock, can be and has been used to measure and evaluate wealth. The ancient Egyptians, for instance, measured wealth based on quantity of wheat possessed by a person. Herding cultures have often used sheep, horses, or cattle as measures of wealth. In the south Indian state of Kerala, number of coco-nut trees a

person owns is regarded his wealth. The coco-nut trees yield a crop of coconuts each season which earns cash to the owner.

The economists define wealth as the total value of a person's assets, minus the debts. It includes the value of physical and intangible assets, such as property and investments. Wealth allows a person to take advantage of favourable investment opportunities which may present themselves at short notice.

Wealth can also include aspects of life beyond finances, such as health, education, relationships, goodwill and personal growth. Wealth can impact many aspects of life, including educational attainment, job opportunities, political power, and overall well-being. Money is wealth but all wealth is not money.

Riches is yet another term used in the context of money and wealth. Human societies differentiate between rich and wealthy. A wealthy person is regarded superior to the one considered rich.

There is an important and essential difference between the natures of money and wealth. The real value of money decreases with time on account of ever-present inflationary tendencies in the price of the goods and services. With passage of time, as inflation impacts, the price of goods and services will increase, and the same amount of money will buy less and less quantity of goods and services.

If there is an inflation of 10 percent, then a sum of 100 rupees today will be worth 90 rupees after one year. After one more year, its value will depreciate by another 9 rupees and it will then be worth only 81 rupees. The true and real value of a principal amount will continue to decline each year depending on the prevailing rate of inflation.



Wealth on the other hand appreciates with time. Consider an example. An amount of 100 rupees deposited in the bank at 10% annual interest will become 110 rupees after one year. The second year will earn 11 rupees by interest and the amount will become 121 rupees. With each passing year the wealth in our example will appreciate by 10 percent. There are other methods of investment available to a person with wealth. He can invest in real estate, housing, business and trade opportunities etc.

For the wealth to appreciate in real terms, it must be invested in such a way, that it earns more than the prevailing rate of inflation.

We should continuously make effort to convert our earned money into wealth. For most individuals it is advisable to save 10 to 15 % of their earnings each month and put the money thus saved into the bank as fixed deposit for a period which earns maximum interest. Your bank will advise you on this count. This should be done each month. When these fixed deposits mature, they can be renewed for another period. The process should be followed for as long as possible.

For those who are young in their careers, the practice of saving each month, investing the savings in fixed deposits and renewing them on their maturity should begin now and in earnest; and continued for as long as it is possible. Such financial discipline, if continued over 20-30 years will make their savings turn into substantial amount of wealth. So substantial that it will surprise them. They will begin to enjoy the benefits of their wealth.

The financial security from the wealth so created, will be in addition to the financial benefits received by a person on his retirement. His own wealth, which he has created by wisely saving and investing will be a source of additional regular substantial income. His wealth will be a real gold mine for meeting the expenses of higher education, marriage, purchasing house etc. or meeting other commitments and responsibilities. Such heavy expenses often arise just before or immediately after retirement. With the financial security of the wealth so created, the wise man and his family will enjoy a happy retired life.

It is time for you to start converting your money into wealth.

Retd. Chief Manager

"ONE LIFE"

Hey Blue Blue, any clue???
Why you dim, add some hue..
You locked the code, lost the zeal
Be rainbow mode, accept the deal..

Written life, a perfect boon
Live this beauty, like a full moon..
No matter what; always carry a smile
Trust the plan, walk a mile ☺

Life is a mockery; to the extreme
Fate is like lottery; Winning is like dream..
BUT
Existing is an option; Living is a choice
This world will hear you; just raise your voice..
After all, ONE LIFE !!!



Gurjeet Singh
Manager
HO Inspection

स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त, 2024

बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज रोहिणी में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें श्री स्वरूप कुमार साहा (प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी), श्री राजीवा (कार्यपालक निदेशक), श्री अरुण कुमार अग्रवाल (मुख्य सतर्कता अधिकारी) तथा अन्य उच्चाधिकारीगणों द्वारा सहभागिता की गई। इस उपलक्ष्य में वृक्षारोपण तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त विभाजन विभीषिका दिवस पर भी प्रदर्शनी लगाई गई।



एमडी एवं सीईओ ध्वजारोहण करते हुए



विभाजन विभीषिका संबंधी प्रदर्शनी



उच्चाधिकारीगण वृक्षारोपण करते हुए

आज का व्यवसाय प्रबंधन



साक्षी वर्मा

आज का व्यवसाय प्रबंधन एक गतिशील और परिवर्तनशील क्षेत्र है जो न केवल पारंपरिक प्रबंधन सिद्धांतों को अपनाता है, बल्कि नई तकनीकी उन्नतियों और बदलती बाजार स्थितियों के अनुरूप ढलता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, डिजिटलीकरण और ग्राहक केन्द्रित दृष्टिकोण ने व्यवसाय प्रबंधन की परिभाषा को व्यापक रूप से बदल दिया है। डिजिटल युग के साथ कंपनियां डेटा-ड्रिवन निर्णय, ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण, नवाचार, स्थिरता, और प्रभावी नेतृत्व पर जोर दे रही हैं। सफलता पाने के लिए व्यवसायों को इन बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने प्रबंधन दृष्टिकोण को लगातार अद्यतित और अनुकूलित करना होगा।

1998 में कोडक कंपनी में लगभग 1,70,000 कर्मचारी काम करते थे और वो दुनिया का 85% फ़ोटो पेपर बेचते थे। चंद सालों में ही डिजिटल फ़ोटोग्राफी ने इस कंपनी को बाज़ार से बाहर कर दिया। इस प्रकार कोडक कंपनी दिवालिया हो गयी और उनके सभी कर्मचारी सड़क पर आ गए। इसी प्रकार अन्य कंपनियां जैसे एचएमटी (घड़ी), बजाज (स्कूटर), डायनोरा (टीवी), मर्फी (रेडियो), नोकिया (मोबाइल), राजदूत (बाईक), एम्बेसडर (कार) आदि ऐसी हैं जिनकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं थी फिर भी बाजार से बाहर हो गईं। इसका कारण यही कि उन्होंने समय के साथ बदलाव नहीं किया। क्या आपको अंदाजा है कि आने वाले 10 सालों में दुनिया पूरी तरह बदल जायेगी और आज चलने वाले 70 से 90 प्रतिशत उद्योग बंद हो सकते हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से आप अनुमान लगा सकते हैं-

1. उबर (ऑनलाइन प्लेटफॉर्म) सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है। उसकी अपनी खुद की एक भी कार नहीं है इसके बावजूद वो दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है।
2. एयर बीएनबी दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी है, जबकि उसके पास अपना स्वयं का एक भी होटल नहीं है।
3. एक जानकारी के अनुसार यूएस में अब युवा वकीलों के लिए कोई काम नहीं बचा है, क्योंकि आइबीएन वॉटसन नामक सॉफ्टवेयर पल भर में ज़्यादा बेहतर कानूनी सलाह दे देता है।



4. वॉटसन नामक सॉफ्टवेयर मनुष्य की तुलना में कैंसर का डायग्नोसिस 4 गुना ज़्यादा सटीकता से करता है।
5. समय के साथ इस प्रकार बदलाव होने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अगले 10 सालों में दुनिया भर की सड़कों से 90% कारें कम हो जाएंगी। जो बचेंगी वो या तो इलैक्ट्रिक कारें होंगी या फिर हाइब्रिड। सड़कें खाली होंगी, पेट्रोल की खपत 90% घट जायेगी। सारे अरब देशों का क्या होगा आप अनुमान लगा सकते हैं।
6. आप उबर जैसे एक सॉफ्टवेयर से कार मंगाएंगे और कुछ ही क्षणों में एक बिना ड्राइवर वाली कार आपके दरवाज़े पर खड़ी होगी। उसे यदि आप किसी के साथ शेयर कर लेंगे तो वो राइड आपकी बाइक से भी सस्ती पड़ेगी। बिना ड्राइवर कार होने के कारण लगभग 99% दुर्घटनाएं होनी बंद हो जाएंगी। इससे कार इंश्योरेंस नामक कारोबार बंद हो जाएगा। ड्राइवर जैसा कोई रोज़गार धरती पर नहीं बचेगा। जब शहरों और सड़कों से 90% कारें कम हो जाएंगी, तब ट्रैफिक और पार्किंग जैसी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि एक कार आज की 20 कारों के बराबर होगी।

आज से लगभग 10 वर्ष पहले ऐसी कोई जगह नहीं होती थी जहां पीसीओ न हों। फिर जब सभी की जेब में मोबाइल फोन आ गया तो पीसीओ बंद होने लगे। इसके बाद पीसीओ वालों ने फोन का रीचार्ज बेचना शुरू कर दिया। अब तो रीचार्ज भी ऑन लाइन होने लगा है। आजकल बाज़ार में हर तीसरी दुकान मोबाइल फोन जैसे सेल, सर्विस, रीचार्ज, एक्सेसरीज, रिपेयर, मेंटीनेंस की है। यह सब अब पेटीएम से हो जाता है। लोग अब रेल का टिकट भी अपने फोन से ही बुक कराने लगे हैं। इस प्रकार पैसे का लेनदेन भी बदल रहा है। अब यह डिजिटल हो गया है। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। अतः समय के साथ बदलने की तैयारी करें। व्यक्ति को समयानुसार अपने व्यापार एवं अपने स्वभाव में भी बदलाव करते रहना चाहिये। इनमें से कुछ परिवर्तन हमारे व्यवसाय को गति प्रदान कर सकते हैं-

- 1. डिजिटलीकरण और तकनीकी उन्नति :** डिजिटलीकरण ने व्यवसाय प्रबंधन को क्रांतिकारी तरीके से बदल दिया है। सॉफ्टवेयर, क्लाउड कम्प्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-AI) जैसे तकनीकी उन्नति ने प्रबंधन प्रक्रियाओं को अधिक कुशल और प्रभावी बना दिया है। डाटा एनालिटिक्स के माध्यम से कंपनियां ग्राहक व्यवहार और बाजार प्रवृत्तियों की गहरी समझ प्राप्त कर सकती हैं, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज और सटीक हो जाती है।
- 2. ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण :** आज के व्यापारिक वातावरण में ग्राहक की प्राथमिकता को समझना और उसके अनुरूप सेवाएं प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्राहक अनुभव (कस्टमर एक्सपीरियंस) प्रबंधन, व्यक्तिगत सेवाओं की पेशकश और ग्राहक फीडबैक पर ध्यान देने से कंपनियां ग्राहक संतोष को बढ़ा सकती हैं और लॉयल्टी को मजबूत कर सकती हैं।
- 3. लचीलापन और नवाचार :** व्यापार जगत में तेजी से बदलते



- परिदृश्य को देखते हुए लचीलापन और नवाचार की आवश्यकता अत्यधिक बढ़ गई है। कंपनियों को अपनी रणनीतियों और प्रक्रियाओं को लगातार अद्यतित और अपनाना पड़ता है। नए उत्पाद और सेवाओं का विकास और अपने मौजूदा बिजनेस मॉडल में सुधार करना कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने में मदद करता है।
- 4. स्थिरता और सामाजिक जिम्मेदारी :** आज के व्यवसाय प्रबंधन में स्थिरता और सामाजिक जिम्मेदारी का महत्व भी बढ़ गया है। कंपनियां पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने, सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देने और नैतिक आचरण को अपनाने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। यह न केवल कंपनी की छवि को सुदृढ़ करता है बल्कि दीर्घकालिक सफलता के लिए भी आवश्यक है।
 - 5. नेतृत्व और टीम प्रबंधन :** सफल व्यवसाय प्रबंधन के लिए प्रभावी नेतृत्व और टीम प्रबंधन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के नेतृत्व को प्रेरणादायक, सहयोगात्मक और परिणाम-उन्मुख होना चाहिए। टीम प्रबंधन में पारदर्शिता, कर्मचारियों के विकास पर ध्यान और एक सकारात्मक कार्य संस्कृति का निर्माण करना आवश्यक है।

अतः आज का व्यवसाय प्रबंधन एक जटिल और विविधतापूर्ण क्षेत्र है जिसमें तकनीकी, ग्राहक और सामाजिक प्रवृत्तियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है। व्यवसायों को निरंतर परिवर्तनशील वातावरण के अनुसार अपनी रणनीतियों को अद्यतित करना होगा, समय के साथ बदलाव करना होगा ताकि वे न केवल प्रतिस्पर्धा में बने रहें बल्कि स्थिरता और सफलता प्राप्त कर सकें। इसलिए, आज का व्यवसाय प्रबंधन न केवल कुशल प्रबंधन की मांग करता है बल्कि नवाचार, लचीलापन, और सामाजिक जिम्मेदारी को भी महत्व देता है।

अधिकारी
प्र. का. सूचना प्रौद्योगिकी

BRANCH INCHARGES MEETING

Zonal Office Chandigarh Organised Branch Incharges Meeting In the Presence of Shri Ravi Mehra, Executive Director & Shri Chaman Lal Shienhmar, Field General Manager and Felicitate the top performer of the Branches.



सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही हेतु बैंक के वित्तीय परिणाम

राशि करोड़ में

मानक	द्वितीय तिमाही वित्तीय वर्ष 2023-24	द्वितीय तिमाही वित्तीय वर्ष 2024-25	वार्षिक विकास-दर
परिचालन लाभ	260	458	198
शुद्ध लाभ	189	240	51
परिसंपत्ति पर प्राप्ति (आरओए)	0.52	0.65	13 बीपीएस
लाभांश (आरओई)	10.47	10.91	44 बीपीएस
अग्रिम-उपज (वाईओए)	8.62	8.75	13 बीपीएस
लागत-आय अनुपात	72.4	62.82	(958) बीपीएस
गैर-ब्याज आय	268	359	91
ऋण-जमा अनुपात	70.32	73.4	308 बीपीएस
स्लिपेज अनुपात	0.45	0.28	(17) बीपीएस
सकल गैर निष्पादित आस्ति (%)	6.23	4.21	(202) बीपीएस
निवल गैर निष्पादित आस्ति (%)	1.88	1.46	(42) बीपीएस
कुल वसूली एवं उन्नयन	594	327	-267
ऋण लागत	(0.05)	0.11	16 बीपीएस
एनआईएम	2.33	2.71	38 बीपीएस
कासा जमा	36327	37744	1417
कुल जमा	116481	124025	7544
सकल अग्रिम	81906	91032	9126
कुल व्यापार	198387	215057	16670

दिनांकित 30-09-2024 तक

राशि करोड़ में

औचलक कार्यालय	कुल जमा (थोक जमा के अलावा)			सकल अग्रिम			कासा जमा (अतलदेय सावधल जमा के अलावा)		
	मार्च 2024	सलतंबर 2024		मार्च 2024	सलतंबर 2024		मार्च 2024	सलतंबर 2024	
		लक्ष्य	उपलब्धल		लक्ष्य	उपलब्धल		लक्ष्य	उपलब्धल
अमृतसर	5741	6208	5965	2077	2200	2120	2472	2662	2486
बरेली	2086	2263	2084	2253	2368	2310	1380	1485	1311
भटलंडा	1997	2168	2041	1651	1741	1709	941	1018	911
भोपाल	2434	2606	2503	1424	1531	1429	1053	1106	1030
चंडीगढ़	7027	7466	7232	2519	2686	2547	2905	3039	2868
चेन्नई	814	880	844	3480	3722	3110	322	339	305
देहरादून	3109	3320	3163	1393	1483	1462	1576	1648	1540
दल्लल - I (सीबीबी के अलावा)	5624	5991	5710	2110	2251	2076	2006	2239	1939
दल्लल - II	7725	8185	7860	1723	1847	2797	2916	3059	2979
फरीदकोट	3459	3754	3529	1971	2075	2074	1596	1721	1559
गांधीनगर	584	632	585	1159	1231	1118	220	232	214
गुरुदासपुर	3877	4198	4030	1569	1651	1587	1759	1892	1776
गुरुग्राम	2424	2590	2510	1872	2020	2082	1130	1184	1112
गुवाहाटी	1738	1861	1460	493	527	505	1037	1088	776
होशियारपुर	3801	4118	3945	1033	1090	1053	1604	1725	1598
जयपुर	1942	2079	1982	2100	2248	2113	900	946	882
जालंधर	6526	7040	6781	1413	1502	1433	2584	2777	2606
कोलकाता	3635	3879	3701	4414	4683	4328	1464	1535	1446
लखनऊ	4058	4331	4199	2788	2959	2895	1924	2015	1920
लुधियाना	4500	4875	4658	2337	2480	2306	2005	2158	1982
मुंबई (सीबीबी के अलावा)	2062	2204	2127	1272	1375	1355	709	964	686
नोएडा	3514	3760	3341	1301	1407	1306	1794	1882	1525
पंचकूला	3404	3697	3479	2152	2270	2139	1532	1648	1550
पटियाला	4036	4373	4148	2518	2639	2526	1521	1635	1488
वलजयवाड़ा	1511	1620	1490	8103	8440	6510	629	659	635
सीबीबी दल्लल	351	374	379	12504	13365	11132	125	135	75
सीबीबी मुंबई	267	285	234	13946	15373	19029	207	220	164
बैंक के कुल आंकड़े	88244	94761	89369	85964	93110	91032	37981	40653	37365

आंचलिक कार्यालयों का कार्य प्रदर्शन

राशि करोड़ में

आंचलिक कार्यालय	खुदरा ऋण			कृषि ऋण			सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम ऋण			गैर निष्पादित आस्तियाँ		
	मार्च 2024	सितंबर 2024		मार्च 2024	सितंबर 2024		मार्च 2024	सितंबर 2024		मार्च 2024	सितंबर 2024	
		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि
अमृतसर	728	783	770	963	994	981	385	417	367	182	171	169
बरेली	361	389	368	1298	1339	1372	593	640	569	259	245	260
भटिंडा	361	393	361	1023	1058	1059	257	280	279	66	63	78
भोपाल	425	457	445	198	205	185	774	837	764	98	93	104
चंडीगढ़	1228	1315	1296	415	429	416	722	779	740	150	140	132
चेन्नई	651	695	670	20	22	20	530	578	491	105	101	103
देहरादून	502	541	525	420	432	403	426	461	463	112	106	99
दिल्ली - I (सीबीबी के अलावा)	790	844	828	132	135	136	948	1019	926	168	167	125
दिल्ली - II	928	993	966	82	85	85	626	678	650	46	43	45
फरीदकोट	382	415	400	1283	1326	1351	307	334	324	98	92	95
गांधीनगर	253	272	288	108	111	102	355	383	367	70	64	67
गुरदासपुर	410	440	421	736	758	736	384	415	390	163	151	157
गुरुग्राम	807	865	852	213	220	215	546	592	516	96	91	87
गुवाहाटी	250	266	272	23	24	15	220	238	218	22	21	25
होशियारपुर	287	309	323	573	594	544	172	187	185	74	70	73
जयपुर	680	730	738	778	803	723	636	692	651	157	148	154
जालंधर	556	598	560	349	359	349	412	449	429	101	95	90
कोलकाता	840	900	822	152	157	160	1047	1120	1089	345	331	374
लखनऊ	896	959	878	272	281	250	1058	1133	1030	249	239	251
लुधियाना	527	571	531	646	668	651	699	759	664	196	188	197
मुंबई (सीबीबी के अलावा)	667	722	673	41	43	89	424	466	390	86	80	81
नोएडा	754	810	762	185	191	186	361	394	355	86	83	66
पंचकूला	650	698	655	803	830	811	425	463	410	146	140	146
पटियाला	582	623	606	1154	1192	1164	420	458	452	101	95	104
विजयवाड़ा	640	686	674	69	71	82	427	462	442	80	75	72
सीबीबी दिल्ली	34	38	37	18	19	18	214	228	218	11	-	6.80
सीबीबी मुंबई	2	5.20	2	69	69	1041	287	330	374	0.03	-	0.04
बैंक के कुल आंकड़े	16034	17618	15684	11938	12914	12085	13154	17891	13161	4665	4257	4141

बैंकिंग उद्योग की चुनौतियां एवं निवारण



विन्नी शर्मा

कि सी भी देश के आर्थिक विकास का मुख्य आधार उस देश का बुनियादी ढाँचा होता है। यदि बुनियादी ढाँचा ही कमज़ोर हो तो कितना भी प्रयास किया जाए व्यवस्था को मज़बूत नहीं बनाया जा सकता है। यही कारण है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विकास एवं उन्नति हेतु किये जाने वाले प्रयासों को बल प्रदान करने के लिये नीति निर्माताओं द्वारा एक ऐसे मार्ग का अनुसरण किया जाता है जिसके माध्यम से सरकार आम आदमी को अर्थव्यवस्था के औपचारिक माध्यम में शामिल कर सके।

यह औपचारिक माध्यम है 'बैंक'। बैंक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। देश में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में बैंक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किंतु विगत कुछ वर्षों से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय बैंकों के समक्ष विभिन्न प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। इस वैश्विक परिदृश्य में स्वयं को सुदृढ़ता से स्थापित करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अतिरिक्त भारतीय बैंकों को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वह इस प्रकार है:-

1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एनपीए के चलते बैंकों को मिलने वाला लाभ कम हो जाता है, जिससे सरकार के पास राजस्व कम पहुँचता है, ऐसे में सरकार की निवेश करने की क्षमता में गिरावट आती है। निवेश कम होने से अर्थव्यवस्था की विकास दर कम हो जाती है, साथ ही बेरोज़गारी की समस्या में बढ़ोतरी होती है।
2. बैंकों में एनपीए की वृद्धि से नए लोगों को ऋण मिलने में कठिनाई होती है, जिससे अर्थव्यवस्था का आकर सिकुड़ता है। जमाकर्ताओं का बैंक पर विश्वास कमज़ोर हो जाता है और वे बैंक में पैसा जमा करने से कतराते हैं। एनपीए के कारण जब बैंक को ऋण की राशि प्राप्त नहीं हो पाती तो उसकी प्रोविजनिंग के लिये उसे मुनाफ़े से एक निश्चित राशि अलग रखनी होती है, जिससे बैंक का लाभ कम होता है जिसका असर ग्राहक सेवाओं तथा उन्नयन पर पड़ता है।
3. त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के तहत बैंक को पूंजी अपर्याप्तता और उच्च एनपीए जैसे कारकों के आधार पर आरबीआई द्वारा पीसीए ढाँचे के तहत रखा जाता है। जिसके परिणामस्वरूप बैंकों की ऋण देने और जमा लेने की क्षमता सीमित हो जाती है।
4. पीसीए लागू होने के बावजूद, बैंकों में वसूली या तो स्थिर रही है या मामूली रूप से बढ़ी है। इस पर यह तथ्य प्रकट हुआ कि आरबीआई को इन बैंकों को एक रोडमैप प्रदान करना चाहिए ताकि वे पीसीए से बाहर आ सकें और सामान्य परिचालन फिर से शुरू कर सकें। इसके अलावा यह पाया कि पीसीए के तहत और अधिक बैंकों को लाने से बैंकिंग क्षेत्र और अर्थव्यवस्था दोनों पर असर पड़ेगा, क्योंकि इससे ऋण उपलब्धता की समस्या और बढ़ जाएगी।
5. राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) का प्रदर्शन दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत बड़े एनपीए का समाधान 270 दिनों की निर्धारित समय अवधि से बहुत अधिक समय ले रहा है। जिससे वसूली बाधित होती है।
6. साइबर सुरक्षा खतरे बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए एक बढ़ती हुई चिंता है, जिससे वित्तीय और प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचने की संभावना है। सुरक्षा बैंकिंग उद्योग की प्रमुख चुनौतियों में से एक है।



7. बाजार प्रतिस्पर्धा में स्वयं को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रबंधन द्वारा कार्मिकों पर अत्यधिक दबाव डाला जाता है जिससे उनका सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन प्रभावित होता है एवं उनकी कार्यक्षमता में गिरावट आती है।
8. डिजिटल बैंकिंग अब विलासिता नहीं बल्कि आवश्यकता बन गई है। 90% से ज्यादा उपभोक्ता डिजिटल बैंकिंग को बैंक चुनने में अहम कारक मानते हैं। सुविधा, कम शुल्क, आसान पहुँच और उपयोग, आपकी सभी वित्तीय सेवाओं को सुव्यवस्थित करना - इसके फ़ायदे व्यावहारिक रूप से अंतहीन हैं। डिजिटलीकरण और उभरती उपभोग प्रवृत्तियों के साथ देनदारियों का चरित्र बदल रहा है, जिसका असर खुदरा जमा पर पड़ रहा है। उच्च क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात रखने वाले बैंकों को तरलता कवरेज में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
9. जब भी कोई नया तकनीकी समाधान सामने आता है, तो कोई न कोई उसे हैक करने की कोशिश करता है। मोबाइल बैंकिंग की बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद, सुरक्षा उल्लंघन एक बड़ा खतरा बना हुआ है। हालाँकि वे अपनी भौतिक शाखाओं में स्वयं-सेवा समाधानों के लिए सुरक्षित प्रमाणीकरण की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि उनके मोबाइल प्लेटफॉर्म डेटा सुरक्षा का समान स्तर प्रदान कर सकें।
10. बैंकों को डाटा गोपनीयता से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उपभोक्ता इस बात को लेकर अधिक चिंतित हो रहे हैं कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी का किस तरह से उपयोग किया जा रहा है। थर्ड-पार्टी वेंडर्स से लेकर लीगेसी सिस्टम तक, बैंकों को डाटा गोपनीयता के मामले में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
11. अनुपालन प्रबंधन से जुड़ी लागत बैंकिंग उद्योग की कई चुनौतियों में से एक है, जो वित्तीय संस्थानों को उनके व्यवसाय करने के तरीके को बदलने के लिए मजबूर करती है।
12. पूंजी की बढ़ती लागत के साथ-साथ निरंतर कम ब्याज दरें, इक्विटी पर घटता रिटर्न और मालिकाना व्यापार में कमी, ये सभी बैंकिंग लाभप्रदता के पारंपरिक स्रोतों पर दबाव डाल रहे हैं।

इन चुनौतियों से निपटा जा सकता है आवश्यकता है, बैंकिंग प्रणाली एवं कार्य परिस्थितियों को रिफॉर्म करने की। संरचनात्मक बदलाव के लिये बैंकरों की ओर से सतर्कता एवं विवेक की आवश्यकता है, जहाँ अनुकूल परिस्थितियों के बीच सावधानीपूर्वक निगरानी आवश्यक है। भेद्यताओं को दूर करने के लिये, सरकार को विनियामक उपायों को परिष्कृत करना चाहिये, बैंकों को विविध ऋण पोर्टफोलियो विकसित



कर सकने में सक्षम बनाना चाहिये, विशिष्ट क्षेत्रों के लिये नियामकों की स्थापना करनी चाहिये और जानबूझकर किये गए डिफ़ॉल्ट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये अधिक अधिकार प्रदान करना चाहिये। बैंकों को नकदी प्रवाह में संभावित व्यवधानों को ध्यान में रखते हुए एसएमई के लिए संभावित जोखिमों का सावधानीपूर्वक आकलन और तैयारी करने की आवश्यकता है। पीसीए के तहत बैंकों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और प्रतिबंधों में ढील दी जाए और उनकी समीक्षा की जाए, खासकर उन बैंकों के लिए जहाँ खुदरा बैंकिंग भी प्रतिबंधित है। धोखाधड़ी के मामले में आरबीआई की जल्दबाजी वाली प्रतिक्रिया, जैसे सस्ते ऋण प्रदान करने वाले लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को बंद करना, से बचना चाहिए, क्योंकि वे ऋण वृद्धि में बाधा डालते हैं। इसके अतिरिक्त कार्मिकों के लिए उचित एवं सौहार्दपूर्ण नीतियां निर्मित की जाएं ताकि उनकी वर्क लाइफ बैलेंस हो सके। भारतीय बैंकिंग के क्षेत्र में, ब्लॉकचेन जैसी प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन से विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण को सुगम बनाने की क्षमता है, जिससे बैंकों पर निगरानी और नियंत्रण अधिक सुव्यवस्थित हो जाएगा।

बैंक ग्राहकों को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए नए और अभिनव उत्पाद और सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वे ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल बैंकिंग, ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों में निवेश कर सकते हैं। बैंक परिचालन को सुव्यवस्थित करके, प्रक्रियाओं को स्वचालित करके और गैर-प्रमुख कार्यों को आउटसोर्स करके लागत कम कर सकते हैं। बैंक अपनी कार्यकुशलता, पहुँच बढ़ाने और अधिक व्यक्तिगत सेवाएँ प्रदान करने के लिए अपने परिचालन, प्रक्रियाओं और ग्राहक संपर्कों को डिजिटल बना सकते हैं। बैंक संभावित हानियों की बेहतर पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रथाओं में सुधार कर सकते हैं, जिससे उन्हें स्थिरता बनाए रखने और निवेशकों को आकर्षित करने में मदद मिल सकती है।

बैंकों के पास धन शोधन से संबंधित संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए प्रणालियां होनी चाहिए। बैंकों को उपभोक्ताओं की सुरक्षा करने वाले कानूनों और विनियमों का अनुपालन करना चाहिए बैंकों को उन कानूनों और विनियमों का पालन करना होगा जो प्रतिबंधित व्यक्तियों और देशों के साथ लेनदेन पर प्रतिबंध लगाते हैं। उपभोक्ता अपनी वित्तीय जानकारी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। बैंक उन्नत सुरक्षा तकनीकों में निवेश करके और सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करके इन चिंताओं को दूर कर सकते हैं। बैंक 24/7 ग्राहक सहायता प्रदान करने और ग्राहकों की पूछताछ का त्वरित जवाब देने के लिए चैटबॉट, एआई और अन्य डिजिटल चैनलों जैसी नई तकनीकों को अपनाकर ग्राहक सेवा में सुधार कर सकते हैं। बैंकों को अपने

कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा की सर्वोत्तम प्रथाओं तथा नवीनतम खतरों और जोखिमों के बारे में जागरूकता पर नियमित प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत डेटा गवर्नेंस ढांचे को लागू कर सकते हैं कि ग्राहक डेटा को डेटा गोपनीयता विनियमों के अनुपालन में एकत्रित, संग्रहीत और उपयोग किया जाए। बैंक के समक्ष चुनौतियां हैं तो उससे निपटने के लिए बेहतर रणनीति बनाकर निपटा जा सकता है। चुनौतियों को पार करके ही विकास की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है।

प्रबंधक

प्र. का. सामान्य संचालन विभाग

Inauguration of New Premises of Branch Meerut Ganeshpur (Mawana)



Smt. Rashmita Kwatra, General Manager inaugurated the Branch



स्वच्छता ही सेवा, 2024



बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में स्वच्छता दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान में डॉ. चरन सिंह (गैर-कार्यपालक अध्यक्ष), श्री स्वरूप कुमार साहा (एमडी एवं सीईओ), श्री रवि मेहरा (कार्यपालक निदेशक), श्री राजीवा (कार्यपालक निदेशक), श्री शंकरलाल अग्रवाल (गैर-सरकारी निदेशक) तथा अन्य उच्चाधिकारीगण उपस्थित रहें।

RBI's Latest Guideline on Wilful Default and Wilful Defaulter



Shantnu kumar

Default means non-payment of a loan availed by a borrower. A wilful defaulter is an entity or a person that has not paid the loan back despite the ability to repay it.

As per the RBI regulations, wilful default covers several broad areas: Deliberate non-payment of the dues despite adequate cash flow and good net-worth, siphoning off funds to the detriment of the defaulting unit, Assets and proceeds have been mis-utilised; Misrepresentation / falsification of records; Disposal / removal of securities without bank's knowledge; Fraudulent transactions by the borrower.

As per an article published in Indian Economy & Markets dated 19.08.2023, top 50 wilful defaulters owe Rs.87,295 Crore to banks. These defaulters include Mehul Choksi's Gitanjali Gems, Rishi Agarwal's ABG Shipyard, REI Agro, and Era Infra Engineering. Of these wilful defaulters, top 10 owe Rs 40,825 crore to scheduled commercial banks, Minister of State for Finance Dr. Bhagwat Karad said in a written reply to the Rajya Sabha. Mehul Choksi's Gitanjali Gems is the biggest wilful defaulter as it owes Rs 8,738 crore to banks. It is followed by Era Infra (Rs 5,750 crore), REI Agro (Rs 5,148 crore), ABG Shipyard (Rs 4,774 crore), and Concast Steel and Power Limited (Rs 3,911 crore). Other wilful defaulters include Rotomac Global (Rs 2,894 crore), Winsome Diamonds and Jewellery (Rs 2,846 crore), Frost International (Rs 2,518 crore), Shri Lakshmi Cotsyn (Rs 2,180 crore), and Zoom Developers (Rs 2,066 crore).

PROCESS OF IDENTIFICATION AND CLASSIFICATION OF WILFUL DEFAULTER:

A lender can identify and classify a person as wilful defaulter by following the procedure directed by RBI in its Master Direction RBI/Dor/2024-25/122 dated 30.07.2024.



All NPA accounts with outstanding amount of Rs.25 Lakh and above will be examined from wilful default angle or as per amendment made by RBI from time to time. If any angle of wilful default is being observed in initial screening, process of classification needs to be completed within 6 months of classification under NPA category.

Following are the standard guidelines prescribed by RBI for classifying an entity or a person as wilful defaulter:

- (A) the borrower has the capacity to honour the said obligations;
- (B) the borrower has diverted the funds availed under the credit facility from lender;
- (C) the borrower has siphoned off the funds availed under the credit facility from lender;
- (D) the borrower has disposed of immovable or movable assets provided for the purpose of securing the credit facility without the approval of the lender;
- (E) The borrower or the promoter has failed in its commitment to the lender to infuse equity despite having the ability to infuse the equity although the lender has provided loans or certain concessions to the borrower based on this commitment and other covenants and conditions.

Classification of wilful defaulter will be done in a structured manner and the evidence of wilful default shall be examined by an identification committee.

Identification committee on its satisfaction of wilful default, will issue a show cause notice to entity/individual asking submission from them within 21 days. After analysing the submission provided by entity/individual, identification committee may forward the case to reviewing committee for classification of wilful default. Identification committee will furnish all the information in writing to review committee (For cases where identification committee believes that the entity/key stake-holders do not qualify for classification as wilful defaulter, such cases need not to be referred to the Review Committee).

The key beneficial owners will be informed about the proposal of classification under wilful default along with the reason thereof. Beneficial owner of entity/individual will be provided an opportunity of representation within 15 days of case being forwarded to review committee.

An opportunity of personal hearing shall be provided to key beneficial owners/individual. Review committee after analysing all details of proposal including facts furnished by identification committee, representation provided by beneficial owner and personal hearing will take a decision.

Above process of classification of wilful default is an in-house proceeding hence, any legal representations will not be allowed.

Decision taken by review committee will be communicated to wilful defaulter in shape of reasoned order.

STRUCTURE OF COMMITTEE LOOKING AFTER WILFUL DEFAULT CASES:

Committee structure along-with rank of officials will be designed under Board Approved Policy. Identification/Review committee must have designated official and competent authority who can pass order on behalf of respective committee.

Independent directors/nominee directors will not be declared under wilful default unless it is conclusively established that default occurred with their involvement.

RBI PRESCRIBED MEASURES AGAINST WILFUL DEFAULTERS:

- ◆ Initiation of criminal proceedings- Lender may proceed for criminal proceedings after understanding the gravity of matter.
- ◆ Publishing of photographs of wilful defaulters- Board

approved guidelines is required for the purpose of publishing photographs.

- ◆ Penal and other measures against wilful defaulters- No additional credit facility to individual/entity to which the person/firm is associated. No facility to the individual/entity up to 5 years even after removal of name from "List of Wilful Defaulter".
- ◆ Restructuring of credit facility will not be allowed after declaration under wilful default till the time name is not removed from the list of wilful default.

OTHER MISCELLANEOUS GUIDELINES:

- ◆ Internal auditors are required to report the cases of wilful default and also recommend the steps to prevent the same in future.
- ◆ Guarantor's liability is equal to principal debtors. If guarantor refuses to pay debts, it will be classified under wilful default.
- ◆ All regulated entities (REs) are required to report the cases of wilful default to CICs.
- ◆ CICs will display the name of suit-filed and non-suit-filed cases on its website.
- ◆ In cases of compromise settlement, name of wilful defaulter will be removed from the list after full payment of the amount of settlement and not after initial payment.
- ◆ A comprehensive investigation must be done for all accounts being transferred to ARCs irrespective of its classification as NPA, having outstanding balance of Rs.25 Lakh and above.
- ◆ Name of wilful defaulter shall be removed from LWD after implementation of the resolution plan under IBC.
- ◆ Role of auditors is very crucial as they need to look for different aspects like, credit appraisal, monitoring end use of funds.

RBI has proposed a structured framework for identification, classification, and reporting of wilful defaulter. Regulated Entities will have a comprehensive guideline and control to handle the cases of wilful default, on the other hand it also provides opportunity of representation to the borrowers.

Senior Manager
Staff Training College
Rohini

बैंक के विभिन्न अंचल कार्यालयों में स्वच्छता दिवस के अवसर पर विभिन्न गतिविधियों/प्रतियोगिताओं/वृक्षारोपण का आयोजन



आंचलिक कार्यालय चंडीगढ़



आंचलिक कार्यालय लुधियाना



आंचलिक कार्यालय कोलकाता





आंचलिक कार्यालय दिल्ली -II



आंचलिक कार्यालय गुरुग्राम



आंचलिक कार्यालय चैन्नई



आंचलिक कार्यालय फरीदकोट

अंचल कार्यालय नोएडा द्वारा डिपॉजिट मोबीलाइजेशन

बैंक के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष डॉ. चरन सिंह के नेतृत्व में डिपॉजिट मोबीलाइजेशन ड्राइव के अंतर्गत अट्टा,सेक्टर-18, नोएडा में डॉ. ललित कुमार शर्मा (उप महाप्रबंधक), श्री संजय दत्ता (सहायक महाप्रबंधक), श्री महेश सभरवाल (आंचलिक प्रबंधक नोएडा) एवं



ड्राइव के अंतर्गत वॉकथॉन का आयोजन

वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में श्री एस. वी. एम. कृष्णाराव (महाप्रबंधक), सुश्री रश्मिता क्वात्रा (महाप्रबंधक), नोएडा और गाजियाबाद के सभी शाखा प्रभारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।



CYBER CRIME: A HOLE IN THE BOAT OF BANKING INDUSTRY AND THE WAY FORWARD



Shourya Soni

Learning Objectives of Case Study

The major objective of this study is to provide a better understanding of various types of cybercrime that are affecting the Banking industry in India along with preventive measures that can be taken to curb cybercrime. The available remedies to victims of cybercrime along with cyber laws will also be contrasted upon for better understanding of cybercrime and its prevention.

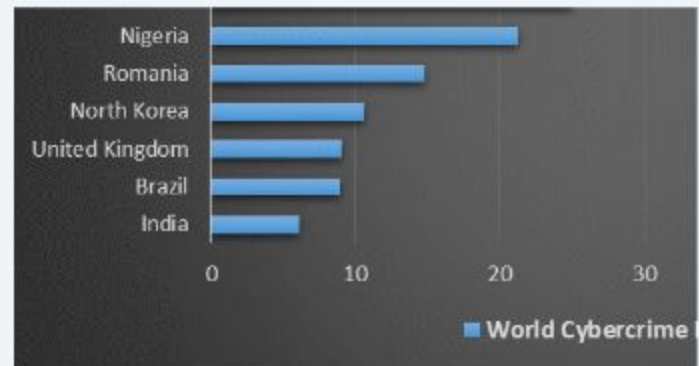
Introduction

Cybercrime has significantly increased in India in the last few years especially with the advancement of technology. The seeds of the technology were sown in the last few years that have reaped a variety of fruits we all enjoy today such as Digital Banking, E-commerce, Digital payments etc. However, in order to enjoy these fruits we must overcome certain challenges with Cybercrime being the prime challenge amongst them. It is indeed the need of the hour to create awareness about emerging cybercrimes and thereby minimize cybercrime in the country.

Evolution of Cybercrime in India and the current state

India ranks number tenth in the world when it comes to cybercrime as per the World Cybercrime Index 2024 as also depicted in Chart 1.0 below and the numbers are increasing very rapidly which is a major cause of concern. In the beginning the absence of any special legal provisions for cybercrime added to the rapid growth in the number of cybercrime being committed in the country. Cyber laws were introduced in India after the enactment of the Information Technology Act 2000 which was amended in the year 2008 and enforced in 2009 to further strengthen the cyber laws in the country. Now as per the latest official data from the National Cyber Crime Reporting Portal nearly 800 online financial frauds are reported in India on daily basis and the number is continuously increasing. India

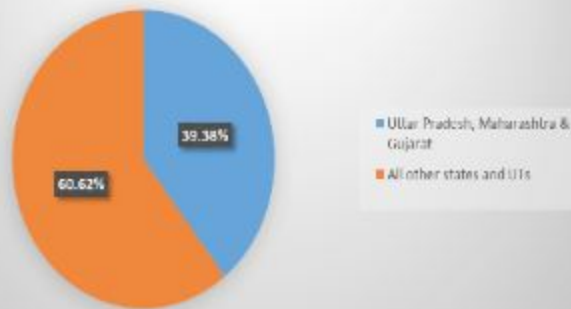
has emerged as a major IT service exporter in the last few years which also added to the rise in Cybercrime as new technologies and skills emerged in the country. Every year Crores of rupees are lost in India due to various types of cybercrimes.



The government has indeed formed various special cybercrime cells to curb cybercrime; however, it is still very difficult to trace the perpetrators of cybercrime. As per the press release by the Ministry of Home Affairs (Annexure I), during the year 2023 a shocking number of 1128265 (Eleven lakhs twenty-eight thousand two hundred and sixty-five) cyber fraud complaints were lodged by the citizens in India for a whopping amount of Rs. 7488.63 Crores. It is pertinent to note that these numbers only reflect the official complaints lodged by the customers wherein a large number of customers are still unaware of the correct procedure to lodge cybercrime complaints and therefore much of the cybercrime in India still stands unreported as well as unaccounted for.

Uttar Pradesh topped the list in India for the most number of official cyber fraud complaints in the year 2023 followed by Maharashtra and Gujarat which is around 40% of the total cyber frauds in India as depicted in Chart 2.0 below. It is pertinent to note that Uttar Pradesh doesn't top the list for the number of Digital transactions in India but has the highest number of cyber frauds reported in the country.

Chart 2.0: Number of Cyber frauds reported in India in the year 2023



Cyber awareness still remains a challenge for the government as the rural and semi-urban areas of the country are still deprived of cyber awareness. Further, the criminals are constantly upgrading their techniques for committing cybercrimes, and thus the public needs to be regularly made aware about the latest techniques of cybercrime and its prevention.

The perpetrators get hope from the complex long process of identifying and tracing out the culprits in case of cybercrime. It is pertinent to note that there are a limited number of investigating officials in the country and the number of cybercrime is increasing very rapidly at an exponential rate. Thus, the investigation often takes a long time to reach its logical conclusion which is posing an alarming system in the country.

Questions arising out of the case study

- ◆ What are the types of Cybercrime that are affecting the Banking industry in India?
- ◆ What preventive measures can be taken to curb Cybercrime and why?
- ◆ What are the available remedies for victims of cybercrime?
- ◆ What are the prevailing Cyber laws in the country and what amendments are required to help reduce cybercrime?

Major types of Cybercrime affecting the Banking Industry

It is of utmost importance to understand the various types of cybercrime which are affecting the Banking industry in India as knowledge and awareness is indeed the key to curbing cybercrime. We are contrasting the most important types of cybercrime as even a brief understanding of this can save an individual lakhs of rupees.

UPI SCAMS

This is the most common cybercrime which is affecting the whole Banking industry and lakhs of customers across the country. The post-demonetization era saw a rapid rise in UPI transactions and so the UPI scams have also risen to a new level in the country. The major challenges currently being encountered in UPI scams are the traceability of the perpetrators and lack of vigilance amongst UPI users. Nowadays UPI is one of the most commonly used methods of digital transaction amongst the customers. Although the average ticket size of UPI transactions still remains low but the number of UPI transactions has exponentially grown in the last few years, especially after the Demonetization.

The victims are often deceived into believing that they are making payment to the genuine beneficiary when in turn the criminals often use spoofed Virtual Payment Address (VPA) to defraud the victims and collect payment to their account. The usage of a virtual payment address makes it very difficult to identify the culprits as there is no Bank detail of the beneficiary such as Bank account number, IFSC code, etc. when the payment is being made to the virtual payment address.

All the Banks in the country are flooded with cybercrime complaints related to UPI.

One of the major issues encountered by account holders is that if they unknowingly accept any digital payment from a person who was involved in cybercrime, then their own account is also put on debit freeze or lien marked by the authorities until the completion of the investigation. The investigation process is complex and long which often lasts from a few weeks to a couple months.

QR Code Scams

With the rise of micro and small entrepreneurs using the QR Codes for accepting payment, a new way has been paved for cyber criminals. QR code scams pose a very alarming threat to the Banking industry in India. In this case, manipulation of the QR code is done by cybercriminals in such a way as to redirect the payment directly to the account of criminals instead of the original beneficiary account.

Sometimes the QR codes are also manipulated in a way that they redirect the users to malicious phishing websites wherein users are tricked to give away their Banking credentials.



Digital Arrest

As the technology advanced so did the methods of cybercrimes. Digital Arrest is one of the newest types of cybercrime that is growing very rapidly in India. Nowadays, cybercriminals are using various social media platforms like Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. to gather information about individuals. The scammers then call the victims impersonating Police or CBI officials and scare the individuals to frame them in various criminal offenses and arrests. The scammers have also started using AI (Artificial Intelligence) generated voices to deceive the users.

Usually, the scammers indulge the victims in video calls and victims are threatened not to leave the video call until they make payment for the closure of investigation. The victims often give in to their fear and pay a hefty sum of money as bribes to these scammers posing as investigating officials.

The victims in such cases are not limited to illiterate customers but highly educated customers like Lawyers, Bankers, Doctors and even IIT professors have also fallen prey to Digital Arrest. When the brain is put under a tremendous amount of stress, the decision-making power of people is often weakened which results in people giving into these fears and not being able to judge the situation properly.

OTP scams

In this type of scam, Cybercriminals deceive customers by posing as courier delivery agents, customer care agents of the Bank, food delivery agents, etc. The perpetrators call the

customers posing as courier/ food delivery agents and ask for OTP from the customer. When the customer denies ordering any courier or food, the perpetrators insist on verifying the OTP with the customer for cancellation of the order, thereby confusing and deceiving the customer.

Phishing

Phishing involves sending deceptive emails, messages, or links to fake websites with the purpose of stealing login credentials/ information of user's bank accounts. The fake websites are crafted by the criminals in such a way that they exactly look like the original website and thus the users are deceived easily by such Phishing attacks.

Phishing is generally done in bulk by the perpetrators targeting multiple users at once; however, the same is also done individually to target high-net-worth individuals.

Malware Attacks

Malware attacks have increased rapidly in the last few years wherein the criminals deceive the users by sending fake cashback links, fake customer support, or convincing the users to install remote access applications in user devices. Installation of such applications allows complete access to user's data and information to fraudsters.

Preventive Measures to Curb Cybercrime

As the saying goes prevention is better than cure, so we need to stop cybercrime from happening rather than going for remedial measures. Prevention is indeed the best medicine against the fast-spreading disease of cybercrime. There are various preventive measures against cybercrime which must all be given due attention for curbing cybercrimes

Cyber Awareness

Cyber awareness is the best shield against cybercrime. It is essential to have basic knowledge about latest cybercrime techniques and keeping up to date about the latest news, applications, etc. Being vigilant about what information is being shared on your social media platforms and to whom it is being shared always helps in reducing the chances of being scammed by cybercriminals.

Online friend requests from strangers on social media platforms must not be accepted to avoid the leakage of private information to potential cyber criminals.



Using Strong Authentication Methods

It is pertinent to note that strong authentication methods provide an extra layer of security against cybercrime. Two-factor authentication methods (Password as well as OTP) must be enabled for all financial transactions. Passwords must not be written anywhere nor to be shared with anyone.

Users should avoid using Banking channels on public Wi-Fi networks and no personal information should be shared over such networks.

Using The Latest Antivirus Software and Firewalls

Mobile devices and computers must be installed with latest firewalls, antivirus software and security patches. All software and applications should only be installed from official websites or verified links to avoid any malware apps.

Being Vigilant

While making any transaction, user must check the URL address for secure sign status. Users must ensure that they are only using HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) while making any online financial transaction and no unverified links should be used.

The users must also properly check the URL address as many scammers have started creating lookalike websites with similar URL addresses to trick online Banking users.

One of the most important checks that is generally ignored by many consumers is to regularly check the Bank statements which may highlight any fraudulent transaction that the consumer is unaware of.

Users must not click on any attachments or links mentioned in spam emails or unverified websites.

While receiving any call from unidentified numbers regarding Digital Banking, OTP verification or any other confusing scenario, users must cross-verify all the details. Users must always keep calm and analyze the situation properly as panicked users will always give in to their fears later realizing that they have been duped.

Cyber Insurance Cover

Buying Cyber Insurance coverage is gaining lot of popularity amongst various businessmen and High net worth individuals in India. Although cyber insurance cover remains limited to only a specific section of society due to lack of awareness but it is indeed gaining popularity in India.

Available Remedies For Victims Of Cybercrime

Contacting The Bank

The first thing to be done after realizing that you have been a victim of cybercrime is to contact your Bank's customer support team and report the cybercrime to the concerned department. The Bank will advise for hotlisting of Debit card or freezing the concerned account to prevent any further cybercrime activity.

Further, customers can lodge complaint to the Bank for availing compensation as per the policy of the Bank. Generally, if the customer has not shared any password, PIN or any other personal detail with the scammers and fraud has taken place without the negligence of the customer then the customers are awarded with full compensation up to the amount of fraud. This is because the Bank takes full responsibility for any security breach or loophole on the Bank's part and thus the customers are secure from any liability when this type of cybercrime is committed.

RBI has already introduced the policy of zero customer liability back in 2017 which clearly states that if the fraud occurs after the customer has reported about compromise of account to the Bank or if no credentials are shared by the customer then the Bank will bear the fully liability of the fraud amount involved.

Lodging complaint on National Cyber Crime Reporting Portal (NCRP)

Customers can also lodge online complaint on National Cyber Crime Reporting Portal by simply visiting their website "https://www.cybercrime.gov.in". First-time customers would need to register on the portal to lodge cybercrime complaint.

The government has made this portal very user friendly and the portal has made it very easy to lodge Cybercrime complaint by just sitting at home.

Lodging Complaint With Local Cyber or General Police Station

Customers can approach their local police station or Cyber Cell to lodge complaint about Cybercrime. It is imperative to note that proper documentation must be maintained by the customers and all the evidence should be preserved to ensure fair trial.

Lodging Complaint With Other Relevant Authorities

If the cybercrime involves any other sector such as Insurance, tradable securities, etc. then the customer can also reach out to the concerned authorities for lodging Cybercrime complaint such as the Securities and Exchange Board of India (SEBI) in case of tradable securities and likewise Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) in case of cybercrime involving Insurance products as well.

In conclusion, it is recommended that as soon as cybercrime is committed an individual must immediately contact the Bank to lodge complaint for freezing/ blocking the concerned accounts or card and then the customer can proceed to lodge complaint at the next level i.e. National Cyber Crime Reporting Portal or the local police authorities etc. Alternatively, the customer can also approach other authorities like IRDAI, SEBI, etc. as this will ensure extra push from these authorities for the timely conclusion of the cybercrime investigation.

Prevailing Cyber Laws In India

Existing Cyber Law framework In India

Cyber laws were introduced in the country under the Information Technology Act of 2000 after approval from the Parliament of India. With the constant modernization of technology and changing scenarios, the Information Technology Act 2000 was amended in the year 2008 which came into force in 2009 with the purpose of strengthening the cyber laws in the country.

The punishment for cybercrime ranges from a particular amount of fine to a specified amount of imprisonment. A penalty of imprisonment for life can also be imposed in cases of Cyber terrorism which is the strictest penalty defined under this act.

On 11th August 2023, the government of India passed the Digital Personal Data Protection Act (DPDP). The act recognizes right of the individuals to protect their personal data and the need to process the personal data for lawful purposes. This act is extraterritorial and so it applies to all entities operating in India as well as outside India if they are involved in processing the data of Indian citizens.

Need for Reforms and Strengthening of Existing Cyber Law Framework In India

Despite India's existing cyber law framework, there are still some limitations and challenges in the existing Information Technology Act such as the absence of clear procedures, definitions and penalties for various cybercrimes.

Further, the conviction rate for cybercrime remains critically low in India as compared to the number of offenses being committed. The major reasons contributing to the low conviction rate in cybercrime are difficulty in tracing the perpetrators and the absence of stringent laws for cybercrime.

Therefore, it is the need of the hour to enact updated cyber laws that cover all aspects of cybercrimes. Special courts and additional tribunals must be established by the government to speed up the trial and judgment procedure in cybercrimes.

Conclusion

It is no doubt a fact that Cybercrime has a serious impact on the Banking industry in India. Cybercrime poses significant challenges to the economic growth and development of the country due to the huge financial losses, business disruptions, security breaches, etc. Therefore, it is the need of the hour to spread Cyber awareness in the country and penetrate the same from rural to metro areas so that cybercrime is prevented from happening. The government and institutions must give cyber awareness a major push amongst the population.

We must use cyber awareness as a sword and preventive measures as a shield against cybercrime. Crores of Rupees can be saved from cybercrime just by being vigilant which in turn will definitely give a boost towards accomplishing our goal of Digital India.

**Officer
ZO Gandhi Nagar**

MoU Signed with Punjab Agriculture University & PCSOA



Our Bank has signed MoU with Punjab Agriculture University for the development of a 'Digital Technology Park's at Ludhiana and Punjab Civil Services Officers Association (PCSOA) to offer exclusive salary account to their members at Ludhiana. The MoU were signed in the presence of Shri Swarup Kumar Saha, MD & CEO, along with Shri Chaman Lal Shienhmar, Field General Manager and Ms. Shilpa Sinha, Zonal Manager Ludhiana.

चीन में बढ़ते आर्थिक संकट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव



विभाष कुमार

दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अर्थात् चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी के गंभीर लक्षण उभरने लगे हैं। हाल के दिनों में, चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए आर्थिक क्षेत्र को वर्ष 2020 (कोविड-19) के लॉकडाउन के समान राहत उपायों की घोषणा की है। देश का रियल एस्टेट इंडेक्स पिछले दो सालों में लगभग 82% गिर चुका है, और अब तक का सबसे लंबा डिफ्लेशन देखा जा रहा है। साथ ही बेरोजगारी की दर कई दशकों के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जिससे देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

चीन की अर्थव्यवस्था की एक बड़ी समस्या रियल एस्टेट सेक्टर है, जो देश की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग एक तिहाई हिस्सा है। 2021 में चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक एवरग्रैंड के डूबने से इस क्षेत्र में गंभीर संकट शुरू हुआ। जिसके उपरांत रियल एस्टेट से संबंधित कंपनियां दिवालिया हो गईं अथवा अपना कारोबार समेट कर इस क्षेत्र से निकल गईं। इस स्थिति ने बैंकों को भी खतरे में डाल दिया है क्योंकि उन्होंने रियल एस्टेट में भारी निवेश किया है। उसके उपरांत भी स्थिति में अपेक्षित सुधार देखने को नहीं मिल रहा है।

चीन के रियल एस्टेट सेक्टर का यह संकट कुछ वर्ष पहले अमेरिका में आई आर्थिक महामंदी (वर्ष 2008) की तरफ संकेत कर रहा है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी मंदी से अमेरिका के आर्थिक गतिविधि में तेज गिरावट थी जो 2007 में शुरू हुई और कई वर्षों तक चली, जिसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ा। इसे 1930 के दशक में आई महामंदी के बाद सबसे महत्वपूर्ण मंदी माना जाता है।

इस शताब्दी की "महामंदी" जो कि अमेरिका की रियल एस्टेट सेक्टर से शुरू होकर समूची अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में लेकर वैश्विक मंदी की शकल ले रही थी। जो दिसंबर 2007 से जून 2009 तक चली, और 2009 में आने वाली वैश्विक मंदी, का कारण बनी। अमेरिका में आर्थिक मंदी तब शुरू हुई जब अमेरिका रियल एस्टेट सेक्टर बाजार तेजी से मंदी की ओर बढ़ गया और बड़ी मात्रा में बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और डेरिवेटिव्स के मूल्य में भारी गिरावट आई।



अमेरिकी में आए इस संकट के पीछे बचत और ऋण (एस एण्ड एल) संकट को प्रमुख कारण के रूप में देखा जाता रहा है। अमेरिका के बैंकों को कई सालों तक इसने आतंकित किया। अमेरिका में बचत और ऋण (एस एण्ड एल) संकट की पृष्ठभूमि 1980 के दशक के मध्य से शुरू हुई, जब अनियंत्रित तरीके से ऋण आबंटन प्रारंभ किया गया।

पिछले लगभग दो दशकों से चीन ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अमेरिका की तरज पर बढ़ाना शुरू कर दिया था। आक्रामक तरीके से ऋण वृद्धि, खराब जोखिम नियंत्रण और संपत्ति में गिरावट के मिश्रण ने 1,000 से अधिक छोटे ऋण संस्थानों की पतन या एकीकरण में के लिए बाध्य होना पड़ा है। चीन के छोटे और मध्यम आकार के बैंक अब उन्हीं संकट से ग्रसित नजर आ रहे हैं। हाल ही में कुछ ही बैंक बंद हुए या दूसरों के साथ विलय हुए।

जून 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान 40 चीनी बैंक गायब हो गए क्योंकि उन्हें या तो बड़े बैंकों में मर्ज कर दिया गया या वे बंद हो गए। अमेरिका में आए एस एण्ड एल संकट के दौरान भी बैंक (ऋणप्रदाता संस्थाएं) इतनी तेजी से गायब नहीं हुए थे जितनी तेजी से चीन के बैंक परिदृश्य से गायब हो रहे हैं।

वैश्विक निवेश बैंकिंग संस्थान जेपी मॉर्गन के अनुसार, चीनी घरों की बिक्री में लगभग 40 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले रियल एस्टेट डेवलपर्स ने 2021 से अपने ऋण दायित्वों का चूक किया है। रिपोर्टों ने

क्रेडिटसाइट्स के आंकड़ों का हवाला दिया है जो दर्शाता है कि चीनी डेवलपर्स ने 2021 से बकाया 175 बिलियन डॉलर के (बॉन्ड) में से 114.6 बिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान नहीं किया है। एक और प्रतिष्ठित वेबसाइट बिजनेस इनसाइडर में हाल ही में अपने प्रकाशित एक रिपोर्ट में एक विशेषज्ञ के हवाले से कहा गया है कि चीन में उपलब्ध खाली घर 3 बिलियन लोगों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त होंगे। रियल एस्टेट संकट के कारण कोविड-19 महामारी और सरकार द्वारा विधि वित्तपोषण पहल जैसे ट्रस्ट फाइनेंसिंग और बॉन्ड जारी करने पर नियामक कार्रवाई है। सरकार को वित्तीय अस्थिरता के जोखिम के बारे में आशंका थी और वह आसमान छूती रियल स्टेट की कीमतों पर लगाम लगाना चाहती थी। इसके कारण इसने रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए फंडिंग विकल्पों को कम कर दिया। उल्लेख किया कि टियर-दो और टियर-तीन शहरों की रियल एस्टेट की कीमतों में क्रमशः 0.2 प्रतिशत और 0.3 प्रतिशत की कमी आई है, जो चीन में लॉकडाउन के बाद आर्थिक व्यवस्था पुनः खुलने के बावजूद रियल एस्टेट बाजार में मंदी का संकेत है।

चीन का रियल एस्टेट बाजार उसके सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30 प्रतिशत के बराबर है, भारत का रियल एस्टेट बाजार अर्थव्यवस्था का लगभग 7 प्रतिशत है। नाइट फ्रैंक के शोध पत्र में कहा गया है कि 1998 में राष्ट्रव्यापी आवास बाजार की स्थापना के बाद से रियल एस्टेट सेक्टर ने चीन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अन्य उद्योगों, विशेष रूप से निर्माण के साथ संपत्ति क्षेत्र के एकीकरण ने इसे चीन के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देने और अर्थव्यवस्था का लगभग एक तिहाई हिस्सा बनाने की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ाया।

भारत के रियल एस्टेट बाजार ने 2008 के संकट के बाद से एक लंबा सफर तय किया है। विशेषज्ञों के अनुसार, भारत ने सबक सीखा और पूरे देश में स्थापित रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरणों के प्रभावी क्रियान्वयन के बदौलत इस सेक्टर को पारदर्शी और उपभोक्ता तथा डेवलपर दोनों के अनुकूल बनाने का प्रयास किया गया है।

देश में कोविड महामारी से पहले घरेलू आय के सापेक्ष घर की कीमतें काफी बढ़ गई थीं, इसलिए क्योंकि उपभोक्ताओं के बीच आकर्षक वैकल्पिक बचत विकल्पों की कमी के कारण अपनी बचत रियल एस्टेट में निवेश करना पसंद किया। देश में फ्लैट और जमीन की कीमतों में निरंतर वृद्धि की उम्मीदों ने उपभोक्ता तथा रियल एस्टेट डेवलपर्स ने तेजी से उधार लेकर इस क्षेत्र में निवेश करना शुरू किया।

कोविड -19 के कारण रियल एस्टेट क्षेत्र में मंदी देखने को मिल। महामारी से पहले के स्तरों की तुलना में फ्लैट की बिक्री में 60 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली थी। चीन में कोविड -19 के

बाद रियल एस्टेट के दामों में जो गिरावट शुरू हुई वो अभी तक जारी है। आने वाले समय में भी चीन के रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए चिंता की लकीर और चौड़ी होती जा रहा है। चीन के रियल एस्टेट बाजार को आने वाले वर्षों में उनके आंतरिक संरचनात्मक कारकों, विशेष रूप से जनसांख्यिकीय परिवर्तन से अतिरिक्त दबाव के चलते इस क्षेत्र में सुधार की संभावना शून्य प्रतीत हो रही है। आने वाले वर्षों में अतिरिक्त नए आवास की आवश्यकता कम हो जाएगी क्योंकि जनसंख्या घट रही है और शहरीकरण धीमा हो रहा है।

चीन का रियल एस्टेट बाजार दबाव में है। चीनी रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा पूरे किए गए अपार्टमेंटों की संख्या पिछले पांच सालों से छह मिलियन के आसपास रही है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार इस बीच, इस उद्योग का मुनाफ़ा गिरकर 2018 और 2022 के बीच के औसत से 50 प्रतिशत तक नीचे गिर गया है। पर्यवेक्षक चीन के रियल एस्टेट उद्योग में गिरावट की बात कर रहे हैं, जिसका असर देश की आर्थिक ताकत पर पड़ेगा।

ग्रामीण और छोटे शहरों के बैंक विशेष रूप से असुरक्षित हैं, क्योंकि उनके पास अपने बड़े समकक्षों के वित्तीय बफर की कमी है। जून 2024 में, 40 छोटे बैंक बड़े संस्थानों के साथ विलय के माध्यम से गायब हो गए, और हेनान प्रांत ने 25 बैंकिंग संस्थानों को प्रांतीय स्तर के ग्रामीण वाणिज्यिक बैंक में समेकित करने की योजना की घोषणा की। ये कदम छोटे बैंकों की कमजोरी को उजागर करते हैं। चीनी नियामक एकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बैंक विफलताओं को प्रबंधित करने के लिए तंत्र की कमी है। एसएण्डपी ग्लोबल का अनुमान है कि उच्च जोखिम वाले ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को पर्याप्त रूप से साफ करने में 4-5 साल लग सकते हैं।

संपत्ति बाजार में संकट ने वित्तीय प्रणाली पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं। क्षेत्रीय बैंक गैर-निष्पादित रियल एस्टेट ऋणों का निपटान करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि बड़े बैंक होटल, रेस्तरां और खुदरा जैसे क्षेत्रों में बढ़ते खराब ऋणों से जूझ रहे हैं। चीनी सरकार से एनपीए अनुपात में गिरावट की रिपोर्ट के बावजूद, चिंताएँ बनी हुई हैं।

बीजिंग ने अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने और संपत्ति बाजार को स्थिर करने के लिए कई उपाय पेश किए हैं। इनमें पुरानी उपभोक्ता वस्तुओं को नए के लिए व्यापार को प्रोत्साहित करने वाली नीति और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को किराए के उद्देश्यों के लिए मौजूदा आवास खरीदने का आग्रह करना शामिल है। हालाँकि, इन पहलों की प्रभावशीलता अभी भी अनिश्चित है। 2024 की दूसरी तिमाही में चीन की जीडीपी वृद्धि दर साल-दर-साल 4.7% तक गिर गई है, जो वर्ष के

पहली तिमाही में 5.3% थी। सरकार ने एक अर्थव्यवस्था को गति देने ले लिए संतुलन कार्य प्रारंभ कर दिया है। रियल एस्टेट बाजार में मंदी के प्रभाव का समुचित प्रबंधन करते हुए निर्यात-संचालित विकास को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है।

साथ ही बीजिंग, शंघाई और शेनझेन सहित चीन के तथाकथित टियर-वन शहरों ने कई सालों से स्थानीय आवास की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक प्रमुख नियम के रूप में गैर-स्थानीय खरीदारों द्वारा घर खरीदने पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। इन चुनौतियों से लड़ने के लिए, चीन के केंद्रीय बैंक ने हाल ही में कई उपाय किए हैं, जिसमें रिजर्व रिक्वायरमेंट में 0.5% की कटौती और मोर्टगेज रेट को घटाने का निर्णय शामिल है। इसके अलावा चीन सरकार ने बैंकों में 142 अरब डॉलर का निवेश किया गया है ताकि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा सके।

चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव में चीन ने अमेरिकी ट्रेजरी सिक्वोरिटीज में अपनी होल्डिंग कम की है जो 15 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका ने चीन से आयात होने वाले कई उत्पादों पर झूटी बढ़ाने का निर्णय लिया है जिससे दोनों देशों के रिश्ते और भी बिगड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त रूस - यूक्रेन, चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव से उत्पन्न युद्ध की स्थिति तथा हाल ही में मिडली ईस्ट (इजराइल- फिलिस्तीन युद्ध) का संकट के चलते चीन की अर्थव्यवस्था में तनाव देखने को मिलेगा।

इन बढ़ते दबावों के जवाब में, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने 24 सितंबर, 2024 को अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार को सहारा देने के उद्देश्य से कई उपायों की घोषणा की। इनमें बेंचमार्क ब्याज दरों में कटौती, बैंकों के लिए आरक्षित आवश्यकताओं को कम करना, बंधक दरों को कम करना और शेयर बाजार में पर्याप्त धनराशि डालना शामिल है। जबकि ये कदम आर्थिक कमजोरी पर बीजिंग की बढ़ती चिंता का संकेत देते हैं, कई अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि एक स्थायी आर्थिक बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए अधिक मजबूत राजकोषीय समर्थन और रियल एस्टेट संकट को दूर करने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यक है। शंघाई, शेनझेन बाजार को बढ़ावा देने के लिए घर खरीदने पर प्रमुख प्रतिबंध हटाएंगे। शीर्ष चीनी शहर शंघाई और शेनझेन में संभावित खरीदारों को आकर्षित करने और अपने कमजोर पड़ते रियल एस्टेट बाजारों को सहारा देने के लिए घर खरीदने पर प्रमुख शेष प्रतिबंधों को हटाने की योजना बना रहे हैं जिससे इस क्षेत्र में सुधार आ सके। यदि ये कदम लागू होते हैं, तो यह संकटग्रस्त रियल एस्टेट क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही मंदी को रोकने के लिए चीनी नीति निर्माताओं द्वारा किया गया नवीनतम प्रयास होगा, जिसने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में विकास पर भारी असर डाला है।

प्रबंधक (राजभाषा)

प्र.का. राजभाषा विभाग

हमें इन पर गर्व है



श्री दिनेश कुमार गोयल, महाप्रबंधक के वाहन चालक श्री प्रवीण इन्सा ने बैंक कार्यालय के बाह्य परिसर में प्राप्त कीमती मोबाइल फोन, जोकि किसी अन्य सरकारी संस्था के उच्चाधिकारी का था, उसे वापस लौटाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की है। इसके लिए रूपांतरण परियोजना विभाग द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया।

In the Presence of General Manager Shri Gajraj Devi Singh Thakur Zonal Office Bareilly Organised Branch Incharges Meeting



IMPORTANT CIRCULARS ISSUED

Date	Circular No.	Subject
HO Accounts & Audit Department		
27/09/2024	512/2024-25	Master Circular on Limited Review - September- 2024
23/09/2024	497/2024-25	FAQ for Branches/Offices related to DO'S & DON'TS of Internal Accounts
23/09/2024	496/2024-25	Incorrect Usage of Internal Accounts
02/09/2024	457/2024-25	Amendment In GST Provisions
01/08/2024	382/2024-25	Department Wise Allocation Of Internal Accounts
HO Credit Department		
08/08/2024	380/2024-25	PSB Scheme on Rent Receivable Product for Corporate Client
HO Credit Monitoring & Policy Department		
17/09/2024	474/2024-25	IBA scheme for recommending transport operators to member banks: additions / renewals / withdrawal / Non-Renewal during the period 1st August, 2024 to 31st August, 2024
31/08/2024	432/2024-25	Extension for the period of empanelment of existing TEV / LIE agencies upto 31.12.2024
24/07/2024	330/2024-25	Policy on Valuation of Property/ Assets charged/ Mortgaged or to be charged to the Bank as Primary and/or Collateral Security
HO Foreign Exchange Department		
30/09/2024	517/2024-25	Notional Rate Circular Effective from 01-10-2024
11/09/2024	465/2024-25	Cessation of FEDAI Membership – Credit Suisse AG
07/09/2024	456/2024-25	Advisory on handling transactions in FCRA accounts
30/08/2024	422/2024-25	Notional Rate Circular Effective from 01-09-2024
18/07/2024	310/2024-25	Categorization of Forex Branches
12/07/2024	303/2024-25	Amendment In Import Policy Under ITC (HS) Code 07019000
12/07/2024	302/2024-25	Release of Foreign Exchange For Miscellaneous Remittances
12/07/2024	299/2024-25	Interest Rates on Foreign Currency (Non Resident) A/C Banks Scheme – Fcnr(B)
HO Fraud Monitoring Department		
20/09/2024	489/2024-25	Advisory to verify caution list of third party entities involved in fraud maintained by IBA
04/09/2024	441/2024-25	Advisory on Referring CFR for Effective Credit and Fraud Risk Management.
03/09/2024	436/2024-25	Compliance of regulatory guidelines in timely reporting of fraud cases to law enforcement agencies
23/08/2024	412/2024-25	Cases of Frauds/Attempted Frauds/Third Party Entities involved in Frauds (Sharing of Information)
05/08/2024	356/2024-25	Cases of Frauds/Attempted Frauds/Third Party Entities involved in Frauds (Sharing of Information)
01/08/2024	298/2024-25	Advisory on cyber fraud
23/07/2024	324/2024-25	RBI Master Directions on Fraud Risk Management in Commercial Banks (including Regional Rural Banks) and All India Financial Institutions
15/07/2024	304/2024-25	Cases of Frauds/Attempted Frauds/Third Party Entities involved in Frauds (Sharing of Information)
08/07/2024	282/2024-25	Cases of Frauds/Attempted Frauds/Third Party Entities involved in Frauds (Sharing of Information)
02/07/2024	265/2024-25	Cases of Frauds/Attempted Frauds/Third Party Entities involved in Frauds (Sharing of Information)
01/07/2024	257/2024-25	Advisory on Cyber Fraud Awareness to Prevent Fraud
HO Human Resources Development Department		
26/09/2024	511/2024-25	Celebration of National Voluntary Blood Donation Day on 1st of October
18/09/2024	479/2024-25	Punjab Sind Bank Officers Promotion Policy- Addendum
18/09/2024	473/2024-25	Training Policy of the Bank
10/09/2024	461/2024-25	Punjab & Sind Bank Officers' Promotion Policy
09/09/2024	459/2024-25	Staff Conveyance Loan Scheme
04/09/2024	443/2024-25	Bereavement Leave Scheme for Employees
30/08/2024	407/2024-25	Aml-kyc and compliance certification by IIBF
20/08/2024	399/2024-25	Separation of employees from banks services during the month of July 2024
19/08/2024	396/2024-25	Frequently asked questions on the provisions of 12th BPS / 9th Joint Note dated 08th March, 2024
19/08/2024	395/2024-25	Formula for fitment of pay of employees on promotion duly implementing the provisions of 12th BPS and 9th joint note
06/08/2024	368/2024-25	Launch of Learning Management System (LMS) - PSB VidyaNidhi
05/08/2024	367/2024-25	Categorization of branches & zones as on 31.03.2024
05/08/2024	364/2024-25	Scheme for reimbursement of fees for courses offered by apex institutes and ed-tech platforms
23/07/2024	328/2024-25	Mandatory leave policy for employees posted in sensitive positions or areas of operations
23/07/2024	327/2024-25	Grant of honorarium to serving inquiry officers/ presenting officers appointed in departmental inquiries
23/07/2024	326/2024-25	Policy/ guidelines on empanelment of retired executives of public sector banks for appointment as inquiry officer in department inquiries
10/07/2024	294/2024-25	Sports policy of the bank
01/07/2024	262/2024-25	Facility to change the option of availment of LFC block for workmen staff

FROM 01.07.2024 TO 30.09.2024

Date	Circular No.	Subject
HO Inspection Department		
26/09/2024	510/2024-25	Salient Features related to Risk Based Internal Audit (RBIA) for Field Functionaries under Inspection & Audit Policy
21/09/2024	495/2024-25	Guidelines on Escalation Matrix as per Bank's Inspection & Audit Policy
21/09/2024	490/2024-25	Zero Tolerance Areas (ZTA)
HO Law & Recovery Department		
21/09/2024	493/2024-25	Update of loan documents in light of latest RBI guidelines
04/09/2024	440/2024-25	Policy for transfer of stressed loans to asset reconstruction companies (arcs)/ permitted transferees including portfolio transfer
04/09/2024	439/2024-25	Policy for management of recovery in non-performing assets/ technical written off accounts
03/09/2024	438/2024-25	Policy for utilization of services of external professionals/agencies/agents for assisting bank in recovery in NPA/two accounts
20/08/2024	398/2024-25	Periodic meetings with chairpersons/ presiding officers of drats/drts
04/07/2024	273/2024-25	Sop for ots proposal and calculator portal
HO Provident Fund Department		
05/09/2024	452/2024-25	Dearness Relief payable to Pensioners for the Period August 2024 to January 2025- Under Punjab and Sind Bank(Employees') Pension Regulations, 1995
25/07/2024	339/2024-25	Group Term Life Insurance Policy for Employees of the Bank for the Period 12.08.2024 to 11.08.2025-Additional Group Term Life Insurance Cover of `5.00 lakh to `20.00 lakh
HO Planning & Development Department		
24/09/2024	500/2024-25	Merger of Branch
24/09/2024	498/2024-25	Opening of New Branch - Siwan (R1636) Under Zone Kolkata
19/09/2024	505/2024-25	Deposit & Customer Service Policy 2024
23/08/2024	413/2024-25	Opening of new Branches.
20/08/2024	400/2024-25	Introduction of "PSB Pink" Debit Card
05/08/2024	363/2024-25	Opening of Full KYC Online Savings Account through PSB UnIC
11/07/2024	297/2024-25	PSB Executive SB Salary Product
11/07/2024	96/2024-25	Introduction of Non Callable Retail Term Deposit Scheme "PSB DHAN KUBER"
05/07/2024	76/2024-25	Opening of New Branch - Rangpo (R1633) Under Zone Kolkata
HO Priority Sector Advances Department		
20/09/2024	492/2024-25	PSB Scheme For Financing To Food And Agro Based Industries Under Msme Clusters (Odop)
20/09/2024	491/2024-25	PSB Scheme For Financing Msme Cluster In Punjab Region
12/09/2024	470/2024-25	Tie-up arrangement with M/s Preet Tractors Pvt. Ltd. and M/s Preet Agro Industries Pvt. Ltd. under PSB Agriculture Infrastructure Fund (PSB AIF)
10/09/2024	464/2024-25	PSB scheme for equipment financing
02/09/2024	445/2024-25	PSB Lakhpati DIDI
06/08/2024	366/2024-25	CGTMSE-Special Provision for Informal Micro Enterprises (IME)
03/08/2024	358/2024-25	Master Directions on Priority Sector Lending (PSL) – Targets and Classification
29/07/2024	343/2024-25	Tie-up arrangement with M/s Malkit Agro Tech Pvt Ltd under PSB Agriculture Infrastructure Fund (PSB AIF) and PSB Scheme for Financing Farm Mechanisation
25/07/2024	336/2024-25	Opening of Web Portal – Dr Ambedkar Central Sector Interest Subsidy Scheme (ACSIS) on Education Loans for overseas studies for OBCs & EBCs – for submission of renewal claims pertaining to June 2024 Quarter (FY 2024-25)
25/07/2024	335/2024-25	Opening of Web Portal- Padho Pardesh Interest Subsidy Scheme- For submission of renewal claims pertaining to June 2024 Quarter (FY 2024-25)
19/07/2024	314/2024-25	PSB GST ease loan (A MSME loan product)
3/07/2024	272/2024-25	"PSB nestle dairy loan scheme"- for financing the farmers enlisted into tie up arrangement with nestle india limited
01/07/2024	259/2024-25	Extension of "psb rise and shine campaign: for empowering ram credit segment" (upto 15.07.2024)
HO General Operations Department		
25/09/2024	507/2024-25	Standard Operating Procedure (SOP) for Opening and Closing of Cash through CBS System
05/09/2024	448/2024-25	SOP for SBSANC Menu for opening of new Society Account
30/08/2024	433/2024-25	SOP E-Kuber 2.0 Configuration
26/08/2024	418/2024-25	Forthcoming General Elections to Legislative Assemblies of Haryana and Jammu & Kashmir, 2024 – SOP on Transportation of clean and genuine cash by banks.
13/08/2024	392/2024-25	Standard Operating Procedure (SOP) for Video based Customer Identification Process (V-CIP)
25/07/2024	337/2024-25	Timely Entry / Verification of Customers Mandate / Transactions
23/07/2024	331/2024-25	Master Direction on Storage of Notes & Coins
06/07/2024	281/2024-25	"नई पहल" campaign for tracing and settling the unclaimed deposits from 08.07.2024 to 14.08.2024.

World Food India 2024



Our Bank inaugurated stall at the world Food India 2024 at Bharat Mandapam, Pragati Maidan, New Delhi. The stall was inaugurated by respected Shri Ravi Mehra, Executive Director, Shri Rajendra Kumar Raigar, General Manager, Shri Gopal Krishan General Manager, Shri Avdhesh Narain Singh, Zonal Manager Delhi-I & Shri Mahesh Sabharwal, Zonal Manager Noida.

International Trade Expo, Greater Noida



At UP International Trade Expo, Greater Noida Hon'ble Shri Rakesh Sachan, MSME Minister, Uttar Pradesh and Shri Nand Gopal Gupta, Minister of Industrial Development, NRI, Export Promotion, Shri Daya Shankar, Transport Minister, Uttar Pradesh inaugurated our Bank's Stall. In this event Smt. Rashmita Kwatra, General Manager, Shri Dinesh Kumar Goyal, General Manager, Shri Kanwar Lal, Deputy General Manager, Shri Mahesh Sabharwal, Zonal Manager Noida and other staff members were present there to represent our Bank.

डिजिटल लेन-देन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव



चंद्रकिशोर पाल

भारत की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदल रही है और इनमें से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन डिजिटल लेन-देन का बढ़ता उपयोग है। 21वीं सदी में डिजिटल तकनीक और इंटरनेट की उपलब्धता के साथ, भारत में डिजिटल लेन-देन ने न केवल व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के लिए बल्कि व्यवसायों और समग्र अर्थव्यवस्था के लिए कई अवसर उत्पन्न किए हैं। नोटबंदी के समय (2016) से डिजिटल भुगतान के प्रति लोगों का झुकाव तेजी से बढ़ा है। विभिन्न एप्स और प्लेटफॉर्म जैसे Paytm, Google Pay, PhonePe, और UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) ने डिजिटल लेन-देन को सरल, सुरक्षित और त्वरित बना दिया है। भारत सरकार ने भी डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से इस दिशा में कई पहल की हैं, जिससे लोगों के बीच डिजिटल लेन-देन को अपनाने की भावना बढ़ी है। इस लेख में, हम डिजिटल लेन-देन के विकास, उसके लाभ, चुनौतियों और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके योगदान का विस्तार से विश्लेषण करेंगे।

डिजिटल लेन-देन का विकास

डिजिटल लेन-देन का विकास एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का संकेत है, जिसने व्यापार, खरीददारी और वित्तीय सेवाओं के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। पिछले दो दशकों में, इंटरनेट और मोबाइल प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास ने डिजिटल लेन-देन को संभव बनाया है। पहले जहां लोग केवल नकद या चेक के माध्यम से लेन-देन करते थे, वहीं अब ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट और विभिन्न डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लेन-देन करना सरल और सुरक्षित हो गया है।

भारत में, प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया पहल और नोटबंदी के बाद, डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू की गईं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) जैसे प्लेटफॉर्मों ने रियल-टाइम में पैसे भेजने का काम आसान बनाया है, जिससे छोटे व्यवसायों और उपभोक्ताओं के बीच लेन-देन तेजी से हो रहा है।

इस प्रकार के लेन-देन से न केवल समय की बचत होती है, बल्कि यह पारदर्शिता और सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। कई देशों में, डिजिटल लेन-देन के जरिए कर संग्रहण और वित्तीय निगरानी में भी सुधार हुआ



है, जो कि आर्थिक अपराधों की रोकथाम में मदद करता है।

लेकिन इसके साथ ही, डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा के खतरे भी बढ़ गए हैं। इसलिए, सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। भविष्य में, तकनीकी नवाचारों के साथ, जैसे कि ब्लॉकचेन और एआई, डिजिटल लेन-देन के क्षेत्र में और भी उन्नति होने की संभावना है। इस प्रकार, डिजिटल लेन-देन का विकास एक सहायक और सतत आर्थिक प्रणाली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

डिजिटल लेन-देन के लाभ

डिजिटल लेन-देन आज के युग की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। इसके कई लाभ हैं जो इसे पारंपरिक लेन-देन के मुकाबले अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनाते हैं। यहाँ हम डिजिटल लेन-देन के प्रमुख लाभों पर चर्चा करेंगे:

1. **सुविधा:** डिजिटल लेन-देन किसी भी समय और कहीं भी किया जा सकता है। आपको लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होती है, बस कुछ क्लिक के माध्यम से लेन-देन पूरा किया जा सकता है।
2. **समय की बचत:** पारंपरिक रूप से किए जाने वाले लेन-देन में समय लगता है, जबकि डिजिटल लेन-देन त्वरित और सरल होता है। यह प्रक्रिया मिनटों में हो सकती है।
3. **सुरक्षा:** डिजिटल लेन-देन अक्सर उच्च स्तर की सुरक्षा प्रोटोकॉल

के साथ होते हैं। एन्क्रिप्शन, दो-चरणीय प्रमाणीकरण, और अन्य सुरक्षा उपाय उपयोगकर्ताओं की जानकारी को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं।

4. **पारदर्शिता:** सभी डिजिटल लेन-देन का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिससे आपको अपने सभी लेन-देन की जानकारी और हिसाब-किताब मिल जाता है। यह आपको अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर समझने में मदद करता है।
5. **कम लागत:** डिजिटल लेन-देन में लेन-देन शुल्क आमतौर पर कम होते हैं। बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा लागू की जाने वाली अधिकांश फीस पारंपरिक लेन-देन की तुलना में कम होती हैं।
6. **आरामदायक भुगतान के विकल्प:** डिजिटल लेन-देन विभिन्न प्रारूपों में उपलब्ध हैं, जैसे मोबाइल वॉलेट, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड आदि, जो उपयोगकर्ताओं को विभिन्न विकल्प प्रदान करते हैं।
7. **त्वरित लेन-देन की प्रक्रिया:** दो पक्षों के बीच धन का ट्रांसफर त्वरित होता है, जिससे किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक लेन-देन में तेजी आती है।
8. **वैश्विक पहुँच:** डिजिटल लेन-देन आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने और पैसे भेजने की सुविधा प्रदान करता है, जो पारंपरिक लेन-देन के मुकाबले अधिक लचीला है।
9. **ऑटोमेशन:** कई डिजिटल लेन-देन प्लेटफॉर्म नियमित भुगतान करना आसान बनाते हैं, जैसे कि बिल भुगतान या सब्सक्रिप्शन सेवाएँ, जिससे समय की बचत होती है।
10. **इंटरनेट आधारित सेवाएँ:** कई डिजिटल लेन-देन सेवाएँ ग्राहकों को बेहतर सेवाएँ और डिस्काउंट्स प्रदान करती हैं, जो पारंपरिक पद्धतियों में संभव नहीं होतीं।

इस प्रकार, डिजिटल लेन-देन न केवल सुविधाजनक और सुरक्षित है, बल्कि यह विभिन्न तरीकों से हमारी वित्तीय गतिविधियों को सुगम बनाता है। इसके लाभों को देखते हुए, यह निश्चित रूप से भविष्य की ओर बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

डिजिटल लेन-देन में चुनौतियाँ :-

डिजिटल लेन-देन ने हमारी आर्थिक गतिविधियों में क्रांति ला दी है। सुगमता, गति और सुविधा के कारण लोग इसे तेजी से अपना रहे हैं। हालांकि, इसके साथ कई चुनौतियाँ भी उभर रही हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए।

1. **साइबर सुरक्षा:** डिजिटल लेन-देन के सबसे बड़े खतरों में से एक है साइबर सुरक्षा। ऑनलाइन लेन-देन के दौरान डेटा चोरी और हैकरों द्वारा ठगी की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने ग्राहकों की जानकारी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सुरक्षा उपाय अपनाने की आवश्यकता

है। डेटा उल्लंघनों के मामलों में, न केवल कंपनियों को वित्तीय नुकसान होता है, बल्कि ग्राहकों का भरोसा भी टूटता है।

2. **तकनीकी मुद्दे:** डिजिटल लेन-देन के लिए इंटरनेट कनेक्शन और तकनीकी उपकरणों की आवश्यकता होती है। कई क्षेत्रों में अभी भी स्थिर और तेज़ इंटरनेट की कमी है। इसके अलावा, तकनीकी गड़बड़ियों के कारण भी लेन-देन में रुकावट आ सकती है। इससे उपभोक्ताओं के अनुभव पर असर पड़ता है और वे असंतुष्ट हो सकते हैं।
3. **वित्तीय साक्षरता:** डिजिटल लेन-देन को अपनाने के लिए उपभोक्ताओं की तकनीकी समझ और वित्तीय साक्षरता आवश्यक है। कई लोग, खासकर वरिष्ठ नागरिक और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग करने में असहज हो सकते हैं। ऐसे में उनकी मदद करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है।
4. **भुगतान प्लेटफॉर्म का असमान वितरण:** जबकि शहरी क्षेत्रों में डिजिटल लेन-देन के लिए कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं है। इससे आर्थिक असमानता की समस्या और बढ़ जाती है। जिन लोगों के पास डिजिटल प्लेटफॉर्म या स्मार्टफोन की पहुँच नहीं है, वे पारंपरिक लेन-देन के तरीके अपनाने को मजबूर हैं।
5. **विधिक और नियामक चुनौतियाँ:** डिजिटल लेन-देन की बढ़ती मात्रा को नियंत्रित करने के लिए उचित विधिक ढाँचे की आवश्यकता है। कई देशों में अभी भी डिजिटल भुगतान के लिए स्पष्ट कानूनों और नीतियों का अभाव है। इससे धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है।
6. **उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा:** डिजिटल लेन-देन में उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यदि कोई लेन-देन गलत तरीके से हो जाता है या कोई धोखाधड़ी हो जाती है, तो उपभोक्ताओं के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए पर्याप्त तंत्र उपलब्ध नहीं है।
7. **मनोविज्ञान:** कई लोग अपने वित्तीय डेटा को ऑनलाइन साझा करने में असहज महसूस कर सकते हैं। यह सामाजिक मनोविज्ञान का विषय है और यह डिजिटल लेन-देन को अपनाने की गति को प्रभावित कर सकता है।

इन चुनौतियों के बावजूद, अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं और उपरोक्त समस्याओं का समाधान करते हैं, तो डिजिटल लेन-देन के लाभों का अधिकतम उपयोग संभव है। इसके लिए संगठनों, सरकारों और उपभोक्ताओं को मिलकर कार्य करना होगा ताकि हम एक मजबूत और सुरक्षित डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ सकें।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव :-

डिजिटल लेन-देन ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई सकारात्मक प्रभाव डालने के अलावा, संभावनाएँ भी प्रस्तुत की हैं:

1. **औसत वृद्धि दर में वृद्धि:** डिजिटल पेमेंट के उपयोग से वित्तीय लेन-देन में तेजी आई है, जिससे अर्थव्यवस्था को व्यापक गति मिली है। यह छोटे और मंझले व्यवसायों के लिए भी सकारात्मक है, क्योंकि उन्हें डिजिटल माध्यमों से तेजी से भुगतान करने का अवसर मिलता है।
2. **रोजगार के नए अवसर:** डिजिटल लेन-देन की बढ़ती प्रवृत्ति ने टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसरों का सृजन किया है। फिनटेक स्टार्टअप्स, ऐप डेवलपर्स और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की मांग में तेजी आई है।
3. **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** डिजिटल लेन-देन के कारण, भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिस्पर्धी बन रहा है। विदेशी निवेशकों के लिए यह

संभावना प्रकट करता है कि उन्हें भारतीय बाजार में डिजिटल प्रारूप में निवेश करने का अवसर मिले।

डिजिटल लेन-देन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव व्यापक है और यह एक सकारात्मक परिवर्तन के रूप में उभरा है। हालांकि, हमें इसके साथ आने वाली चुनौतियों का भी सामना करना होगा। सरकार, निजी क्षेत्र और समाज के लिए यह आवश्यक है कि वे संयुक्त रूप से डिजिटल साक्षरता बढ़ाने, बुनियादी ढांचे में सुधार करने और सुरक्षा उपायों को सख्त करने का प्रयास करें। ऐसा करने पर ही हम भारत को एक डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने में सफल होंगे, जो समृद्धि और विकास का नया अध्याय खोलेगा।

डिजिटल इंडिया का सपना तभी साकार होगा जब हम सभी इस परिवर्तन में योगदान दें और इसे स्वीकार करें।

प्रबंधक

प्र.का. अग्नि सुरक्षा विभाग

Our bank signed MoU with Indian Air force



With a commitment to serve our Air Warriors MoU has been signed and exchanged by AVM Updesh Sharma VSM ACAS (Accts & AV) Air HQ and Shri Gopal Krishan, General Manager.



Move to Market Campaign drive conducted by Zonal Office Delhi-II under the support and guidance of respected Shri Ravi Mehra, Executive Director, Shri Rajesh C Pandey, General Manager, Shri Gopal Krishan, General Manager & Shri S.V.M Krishna Rao, General Manager.



Free-Health Check-Up Camp (सफाई मित्र सुरक्षा शिविर) got conducted at the office of MCD Mayor by Zonal Office Delhi-II.



Shri Gopal Krishan, General Manager, Shri Sanjay Prakash Srivastava, Zonal Manager Delhi-II felicitate Dr. Shelly Oberoi (Mayor, MCD) with plant.



ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 13 ਨਵੰਬਰ ਸੰਨ 1780 ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ (ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਖੇ, ਸ਼ੁਕਰਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਆਪ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1792 ਤੋਂ 1797 ਤਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੰਨ 1797 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜਾਗੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਆਪ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਦ-ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਇਕ ਉੱਘੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਬਣੇ।

ਸੰਨ 1801 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਹਥੋਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਲ ਸੰਨ 1799 ਤੋਂ 1849 ਤਕ ਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਵਲ ਝਾਂਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਜੁਟਾ ਸਕਿਆ।



ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਾਜ-ਤਿਲਕ ਹੋਇਆ

ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਅਪਣੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਨਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। 21 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 'ਮਹਾਰਾਜਾ' ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 'ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ।

ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ, ਉਹ ਇਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਦ ਦੇ ਅਤੇ ਕਣਕ-ਭਿੰਨੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅੱਖ ਚੇਰਕ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਚੇਰਕ ਦੇ ਦਾਗ ਸਨ। ਪਰ ਆਪ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੋਅਬ-ਦਾਬ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੇਹਦ ਦਿਲ-ਖਿਰਵੀਂ ਸੀ। ਆਪ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਆਪ ਵਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਰਮ ਅਤੇ ਵਿਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਤੇ ਵਿਆਲਤਾ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਅਜ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਆਪ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਂਗ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਇਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਸ਼ਾਸਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਲਈ ਸਤਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ, ਉਸਦੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ

ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਚਿਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਇਕ ਉੱਘੇ ਜਰਨੈਲ, ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ, ਕੁਸ਼ਲ ਘੋੜਸਵਾਰ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਕ ਸਨ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਾ ਦਇਆ ਅਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਗੋਂ, ਜਿਸ ਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਉਸਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਗੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ।

ਆਪ ਨੇ ਅਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਨ। ਪਠਾਣ-ਅਫਗਾਨ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਉਭਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਦੇ-ਲੁਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਪਾਈ।

ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਨੇ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਸੁਢੇਰੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਖਲਾਈ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਯੋਰਪੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਾਰਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਲਾਰਡ ਲੇਕ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਪੱਧਤੀ ਅਤੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਨੇ ਅਫਗਾਨ ਹਾਕਮ ਕੁਤੁਬੁ ਦੀਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਕਸੂਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗੜਾ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਅਫਗਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ। ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਓਧਰ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਮਰੂਦ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਫਗਾਨੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਿਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਕ ਵਿਰਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਖਾਲਸਾ' ਜਾਂ 'ਪੰਥ-ਖਾਲਸਾ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਨਿੰਘਮ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ: 'ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।'

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਸ਼ਲ ਘੋੜਸਵਾਰ, ਇਕ ਚੰਗੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਸ਼ਾਸਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪੱਖੋਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਚੁਕੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ। ਆਪਨੇ ਨਵਾਂ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਕਰਵਾਏ। ਸਗੋਂ, ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਕਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ 'ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ' ਆਖਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ, ਸਤਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਦਿੱਖ ਲਈ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੌਗਤਾਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਲਈ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੀਰਥਸਥਾਨ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਲਈ 22 ਮਣ (ਲਗਭਗ 880 ਕਿੱਲੋ) ਸੋਨਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ।

ਇਕ ਵਾਰੀ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੁਸ਼ਨਵੀਸ ਨੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਵਾਬਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਸਭ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਨਵੀਸ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਖੁਸ਼ਨਵੀਸ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵੇਖੀ। ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਖੁਸ਼ਨਵੀਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹੀ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ ਵਿਚ ਰਖ ਵਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਉਦਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁੱਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਇਸਦੀ ਇਤਨੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਇਕ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਕੀਰਣਤਾ, ਤੰਗਦਿਲੀ ਅਤੇ ਤੁਅੱਸਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਬਸਾਂਝੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਆ ਦਾ ਸਨੇਹ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਵਾਂਗ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਪੰਡਤਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਤੇ ਕਦਰਦਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ।

ਆਪਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਤਕਾਰ ਸੀ। ਆਪ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਕਦ-ਬੁਤ, ਰੰਗ-ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਸਗੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਰਜਾ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ-ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਰ-ਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਧਰਮ- ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਅਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ੫੮ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 27 ਜੂਨ 1839 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ।

ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਸ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੰਵਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੋਨਹਾਰ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਵਕਤ ਮੌਤ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਪਣੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸੁਚੱਜਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਸ਼ਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਅਣਖੀ ਸੂਰਬੀਰ ਸ਼ਾਸਕ ਵਾਂਗ ਸਦਾ ਜਾਦ ਰਖੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਪੁੱਤਰੀ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ (ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ)

Our Bank signed MoU with Indian Coast Guard for Defence Salary Package. Shri Ravi Mehra, Executive Director along with Shri Gopal Krishan, General Manager signed MoU at their Delhi office.



ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਸੰਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਝਲਕਿ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
(ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਉਪਕਰਮ)



Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

SPECIAL DAYS FIXED DEPOSIT

Unlock Exclusive Returns
Higher Rates, Bigger Gains

222 DAYS

6.30%
p.a.

333 DAYS

7.15%
p.a.

444 DAYS

7.25%
p.a.

666 DAYS

7.30%
p.a.



* T&C apply

Senior Citizen 0.50% & Super Sr.Citizen 0.65% extra

"BIG REWARDS . BIGGER SAVINGS"

PSB UDYAM CURRENT ACCOUNT



PLATINUM

GOLD

SILVER

FEATURES

FREE CHEQUE
BOOK/
DD/NEFT/RTGS
FACILITY

FLEXI
FACILITY (AUTO
SWEEP-IN &
SWEEP-OUT)

FREE
INSTALLATION
CHARGE OF
BHARAT/
UPI QR CODE

FREE
PREMIUM DEBIT
CARD WITH
ATTRACTIVE
FEATURES

PoS RENT
WAIVED*



Scan QR code
to download
PSB UniC



Scan QR code
to download
PSB UniC

* T&C apply